स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

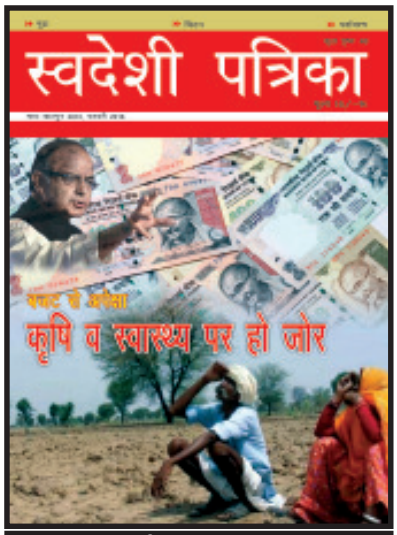

वर्ष–24, अंक–2
माघ–फाल्गुन 2072, फरवरी 2016

संपादक
विक्रम उपाध्याय

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 34-37

कवर तृतीय पेज 39
कवर चतुर्थ पेज 40

आवरण कथा – पृष्ठ–6

बजट 2016–17

कृषि और स्वास्थ्य पर हो जोर

डॉ. अश्वनी महाजन

1 कवर पेज
2 कवर द्वितीय पेज
09 **आवरण कथा–2**
बैंकों पर भारी दबाव ..... **अभिजीत लेले**
10 **आवरण कथा–2**
घटेगा विनिवेश का लक्ष्य! ..... **अरूप राय चौधरी**
11 **अर्थव्यवस्था**
भारत सरपट दौड़ेगा ड्रैगन डांवाडोल ..... **धर्मेन्द्र भदौरिया**
13 **पर्यावरण**
प्रकृति व पर्यावरण के प्रति असहिष्णुता घातक ..... **प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा**
17 **नहीं चलेगा अब ढुलमुल रवैया** ..... **सुनीता नारायण**
18 **मुद्दा**
भारत को नहीं चाहिए जीएम सरसों ..... **देवेन्द्र शर्मा**
21 **सूखा**
बुंदेलखंडः खेत के साथ सूखा आंखों का भी पानी ..... **पूजा सिंह**
23 **चिंतन**
धूमिल होती संसद की गरिमा ..... **विद्यानन्द आचार्य**
26 **विचार**
स्टार्ट–अपः नए उद्यमों का रोडमैप ..... **डॉ. भरत झुनझुनवाला**
28 **शिक्षा**
आधुनिक शिक्षा बनाम गुरूकुल पद्धति ..... **मनोज भारत**
30 **दुर्दशा**
भारत में किसान आत्महत्याओं का सच ..... **विवेकानंद माथने**

पाठकनामा

अब तो पाक पर भरोसा छोड़े

हेडली की अमरीका से यह स्वीकारोक्ति की मुंबई में हमले के लिए पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने लश्कर–ए–तोईबा के साथ मिलकर योजना बनाई थी, भारत को अब यह जिद छोड़ देनी चाहिए कि पाकिस्तान हमारे साथ किसी भी तरह का सहयोग करने के लिए तैयार होगा। पाकिस्तान में चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, चलती तो वहां की सेना की ही, और पाकिस्तान सेना अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर आज भी भारत को तबाह–बर्बाद करने के मंसूबे बना रही है और भारत पर हमले करवा रही है। नवाज शरीफ या तो अंधेरे में है या जान–बूझकर भारत को गुमराह कर रहे है कि उनका देश आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति पर चल रहा है। हेडली द्वारा अमरीका की जेल से पाकिस्तान से हमले की सारी जानकारी प्रदान करने के बाद अब भारत को पाकिस्तान पर कतई भरोसा नहीं करना चाहिए।

प्रवीण दीक्षित, *बागपत, उत्तर प्रदेश*

❋❋❋❋❋

स्वदेशी जागरण मंच से ही उम्मीद

जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है उससे तो यही लगता है कि विदेशी कंपनियों पर आश्रित नीतियों के रहते हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। 1991 में उदारीकरण की शुरूआत के बाद आज तक इस बहस में देश उलझा हुआ है कि घरेलू संसाधनों और पूंजी से देश का विकास होगा या विदेशी संसाधनों और विदेशी पूंजी से। हम लगातार विदेशी पूंजी पर अपनी निर्भरता बढ़ाते जा रहे हैं। परिणाम यह मिला है कि कुछ अमीर लोग बहुत अमीर हो गये लेकिन जो गरीब थे, वे ओर ज्यादा गरीब होते चले गये। एक–एककर सभी प्रमुख उद्योगों पर विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। चाहे वो ऑटो मोबाईल क्षेत्र हो या टेलीकॉम, सभी जगह विदेशी कंपनियों का बोल–बाला है। सरकार के पास दिखाने के लिए सिर्फ मनरेगा और किसानों से संबंधित कुछ नीतियां रह गई है, जो भारी सब्सिडी के भरोसे चलती हैं। स्वदेशी जागरण मंच को एक बड़ा अभियान चलाना होगा।

सचिन चौधरी, *झारखंड*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

एक परिवार अपनी जिद के लिए देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है।

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

जिस एजेंडे पर कश्मीर में पीडीपी-बीजेपी की सरकार बनी उसमें आठ महीने में क्या ऐसा बदलाव आ गया कि संख्या होने के बावजूद सरकार नहीं बन पा रही है।

उमर अब्दुल्ला
एनसी नेता

अमरीकन मुस्लिम राजनैतिज्ञों को इस झूठी थ्यौरी को गलत ठहराना होगा कि पश्चिम मुस्लिमानों को दबा रहा है।

बराक ओबामा
अमरीका राष्ट्रपति

भारत हमेशा से अपनी सहनशीलता के लिए जाना जाता है लेकिन जब पठानकोट जैसे हमले हो तो हमे ऐसा लगता है कि जवाब देने का समय आ गया है।

अक्षय कुमार
फिल्म अभिनेता

संपादकीय

काश ऐसा बजट होता!

दो साल बीत गए इंतजार करते करते करते अच्छे दिन दूर तक दिखाई नहीं देते। इस बीच तालियों की गड़गड़ाहट खूब सुनाई पड़ी है। कभी मेक इन इंडिया के लिए तो कभी स्टार्ट अप इंडिया के लिए। कभी जनधन योजना के लिए तो कभी स्वच्छ भारत के लिए। पर नहीं नहीं सुनाई पड़ रही है तो वह बेरोजगारों की आवाज है, किसानों की कराह है और मजूदरों का दर्द है। काश इस बार के बजट में इन लोगों के हालात बदल जाते। बजट में वित्तमंत्री जी तमाम आकड़े ऐसे गिनवायेंगे जिसमें ऐसी ध्वनि होगी की देश बहुत तरक्की कर रहा है। चीन बीमार हो चुका है और हम जवान होते जा रहे हैं, कुछ आकड़े ऐसे भी होंगे जिनसे यह साबित करने की कोशिश होगी कि पूरी दुनिया का पैसा हमारे यहां ही चल कर आ रहा है। बजट में कुछ ऐसे आकड़ें भी होंगे जिनके जरिए यह समझाने की कोशिश की जाएगी कि सरकार ने जनकल्याण के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। इस बार के बजट में आर्थिक विकास का दावा जीडीपी जैसे शब्दों के जरिए जनता के दिमाग में न ठूंसा जाए, बल्कि यह बताया जाया जाए कि दो साल के मोदी शासन में कितने करोड़ कितने लाख या कितने हजार लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल कर मध्य आयवर्ग का तमगा लेने में सफल रहे हैं। यह न बताया जाए कि अर्थव्यवस्था का मूल आधार काफी मजबूत है, बल्कि यह बताया जाए कि बुनकरों ने किस तरह अपनी हालात ठीक कर ली है, किसानों की हसीं किस तरह लौट आई है या समझाने की कोशिश की जाए कि दो साल में कितने लोगों ने कल कारखाने लगा लिए कितने लोगों ने अपना नया व्यवसाय शुरू कर दिया या कितने लोग ईधर–उधर मजगमारी के बजाय सरकारी सेवाओं में चले गए। काश इस बजट में स्कीमों के बजाय अभी तक की घोषित योजनाओं को ही ईमानदारी से लागू करने का वर्ष घोषित कर दिया जाए। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी भूख और सबसे बड़ी आवश्यकता भोजन। भोजन का अधिकार संसद ने देश को दे दिया है, पर क्या भोजन सबको सहज उपलब्ध है। कहने को सरकार एक लाख 24 हजार करोड़ की खाद्य सब्सिडी दे रही है। यानी प्रति व्यक्ति लगभग 1000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। फिर भी लोग भूखे सो रहे है। जाहिर है ये सब्सिडी कहीं और जा रही है। पीडीएस के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या इस राशि को भी कैश ट्रांसफर में नहीं बदला जा सकता। या फिर सरकारी गल्ले की दुकान या सरकारी सुपर स्टोर जैसी कोई व्यवस्था। फिर उसमें रियायती दर सिर्फ गेहूं और चावल ही क्यों, दालें–सब्जियां और मसाले भी हो सकते हैं। इसमें भी हम यह आह्वान कर सकते हैं कि लोग अपनी सब्सिडी किसी और को दान कर दें। काश इस बजट में शिक्षा के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए जाते। मसलन गांवों और सरकारी स्कूलों में उसी स्टैडर्ड के शिक्षक होते जो बड़े शहरों के बड़े कान्वेंट स्कूल में होते हैं और शहरों या बड़ें कान्वेंट में उतनी ही स्कलू फीस होती जितनी गांवों के लोग वहन कर पाते हैं। आज की शिक्षा पद्धति दो भारत बना रही है। एक वह भारत जो न तो विकास के दौर में शामिल हो पाता, न देश के जीडीपी में कोई योगदान कर पाता। वह शिक्षा व्यवस्था के दोहरेपन का शिकार लगातार होता आ रहा है। एक दूसरा भारत जो अपने पैसे के बदौलत न सिर्फ उन्नत और सहज शिक्षा प्राप्त करता है, बल्कि वह अपनी पहुंच के बदौलत इस व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान भी करता है। एक के लिए टूटा–फूटा स्कूल और आधे अधूरे शिक्षक उपलब्ध हैं तो दूसरे के लिए शानदार इमारत और शिक्षा की सभी आधुनिक सुविधाएं। क्या एक देश के नाते हम अपने नागरिकों से भेदभाव नहीं कर रहे हैं। इस बीच शेयर बाजार भी गिर रहा है और सोने चांदी के कारोबार में भी मंदी है। रियल एस्टेट अब तौबा करने वाला सेक्टर बन गया है। जो लोग पैसे के बदले पैसे कमाते रहे हैं उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। वे किसी भी नये निवेश को जोखिम मानकर मुंडी मार बैठ गए हैं। हमारा कॉरपोरेट सेक्टर लायबिलिटी के बोझ से दबा पड़ा है। वह भी सरकार की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। सरकार के पास विकल्प तो हैं लेकिन वित्तमंत्रालय और रिजर्व बैंक की चिंता कहीं और हैं। वित्तमंत्रालय अर्थव्यवस्था की रोजी पिक्चर दिखा कर विदेशी निवेशकों को भारत में लाने का प्रयास कर रहा है। भले ही आंतरिक रूप से हम कमजोर होते जा रहे हैं। तो रिजर्व बैंक की चिंता डूब रहे बैंकों को उबारने की है। विता मंत्रालय इसलिए भारी सार्वजनिक निवेश से बच रहा है कि उसके लक्षित राजकोषीय घाटा तीन फीसदी से चार फीसदी तक बना रहे उससे उपर न जाए साथ ही इस बात की भी चिंता कर रहा है कि कैसे जीडीपी दर भी सात फीसदी हासिल कर ले। हालात पहले मुर्गी कि पहले अंडा की हो गई है। पहले सरकार हालात सुधरने का इंतजार करे और फिर जोखिम ले या जोखिम लेकर अर्थव्यवस्था की पहिया तेज घुमाए और हालात सुधारे। ❑

बजट २०१६-१७

कृषि और स्वास्थ्य पर हो जोर

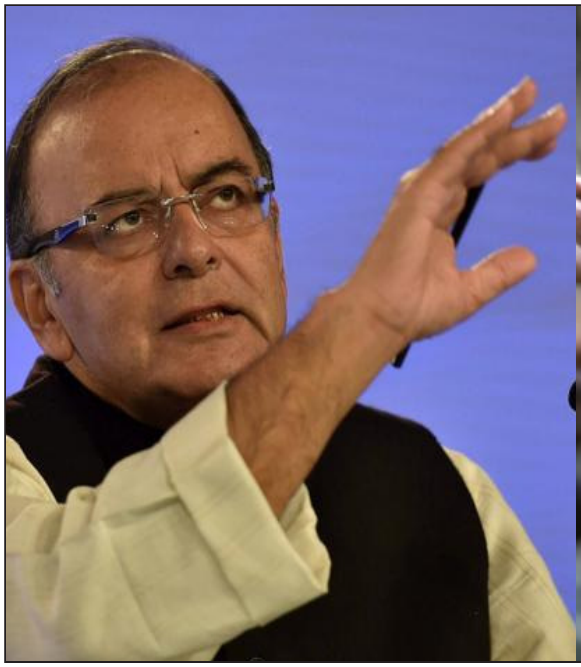

वित्तमंत्री 28 फरवरी को बजट 2016–17 प्रस्तुत करेंगे। पिछले साल बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा था कि वर्ष 2015–16 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.9 प्रतिशत रहेगा, लेकिन 2016–17 में इसे घटा कर 3.5 प्रतिशत तक लाया जाएगा। देखा जाए तो महंगाई को काबू रखने के लिए राजकोषीय घाटे को काबू रखना इसलिए जरूरी है। आमतौर पर खर्चों में कटौती के पीछे सरकार का यही तर्क रहता है कि उसके पास साधन कम है और यदि खर्च ज्यादा किया तो उसका असर राजकोषीय घाटे पर पड़ेगा और इस प्रकार महंगाई पर भी। पिछले साल के केन्द्रीय बजट में कुल 17.77 लाख करोड़ रूपए का खर्च करने का प्रावधान था, जो उससे पिछले साल के बजट से लगभग 17 हजार करोड़ रूपए कम था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी साल का केन्द्रीय बजट उससे पिछले साल के बजट से छोटा बना हो। राजकोषीय घाटे को सीमित रखना और राज्यों को केन्द्रीय करों से ज्यादा हिस्सा देने की मजबूरी इसका कारण बताए गए थे।

आमतौर पर खर्चों में कटौती के पीछे सरकार का यही तर्क रहता है कि उसके पास साधन कम है और यदि खर्च ज्यादा किया तो उसका असर राजकोषीय घाटे पर पड़ेगा और इस प्रकार महंगाई पर भी।

– डॉ. अश्वनी महाजन

बढ़ रहा है राजस्व

वर्ष 2015–16 अर्थव्यवस्था के लिए कुल मिलाकर शुभ कहा जा सकता है। पिछले साल से जीडीपी में बेहतर ग्रोथ, पिछले 14 महीनों में लगातार शून्य से कम रहती थोक मुद्रा स्फीति, तेल की घटती हुई अंतर्राष्ट्रीय कीमतें; ये सभी सरकार के लिए राहत देने वाली रही। वर्ष 2015–16 में कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें पिछले वर्षों के मुकाबले एक तिहाई से भी कम रह गई। मौके का लाभ उठाते हुए सरकार ने घटती तेल कीमतों के मद्देनजर तेल पर एक्साईज ड्यूटी बढ़ा दी और तेल की कीमतें थोड़ी घटाई। इसका असर यह हुआ कि 2014–15 में जहां पेट्रोलियम एक्साईज ड्यूटी से केन्द्र सरकार को 78454 करोड़ रूपए ही प्राप्त हुए थे, वर्ष 2015–16 में यह राशि बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रूपए हो जाएगी। यही नहीं अब सरकार और तेल कंपनियों को पहले से कहीं कम पेट्रोलियम सब्सिडी का भार सहना

पड़ेगा। यानि एक तरफ राजस्व में वृद्धि और दूसरी ओर सब्सिडी बिल में कमी, केन्द्र सरकार को दोहरे लाभ मिल रहे हैं।

वेतन आयोग को लागू करने का भी दबाव

सातवें वित्त आयोग को लागू करने के लिए सरकार को 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का अतिरिक्त प्रावधान बजट में करना पड़ेगा। उधर एक रैंक एक पेंशन को लागू करने के लिए भी सरकार को लगभग 40 से 50 हजार करोड़ रूपए

लेकिन सार्वजनिक निवेश को बढ़ाए बिना देश में ग्रोथ को गति देना संभव नहीं, ऐसा सरकार भी मानती है।

इतिश्री मान लेती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हों, अच्छी नस्ल के बीजों की उपलब्धता हों, पशुपालन, मुर्गी पालन या कृषि की सहयोगी गतिविधियां हों, भंडारण हो या कोल्ड स्टोरेज; पिछले सालों में सरकार का इन सब मदों पर खर्च बहुत कम हो रहा है। पिछले सालों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी लगभग रूका रहा। यह सही है कि मोदी सरकार के आने के बाद सिंचाई सुविधाओं पर अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन जरूरत इस बात की है

- **चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की दर 7.4 फीसदी होने का अनुमान**
- **कृषि विकास दर में गिरावट इस वर्ष पहली छमाही में कृषि विकास दर सिर्फ 2 फीसदी रही।**
- **औद्योगिक उत्पादन में भी भारी गिरावट, नवंबर 2015 में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर सिर्फ ३.२ फीसदी।**
- **निर्माण उद्योग वृद्धि दर नकारात्मक स्थिति में पहुंची। नवंबर में निर्माण वृद्धि दर -४.४ फीसदी।**
- **उपभोक्ता सेंटीमेंट अभी भी नकारात्मक स्थिति पर। बाजार में मांग में उढाव की कमी।**
- **रिजर्व बैंक द्वारा पिछले कुछ समय में ब्याज दर में १.२५ फीसदी कटौती के बावजूद बैंक ग्राहकों को सस्ता लोन देने को तैयार नहीं।**
- **हाउस होल्ड मुद्रा स्थिति की दर १० फीसदी के आस-पास रहने की संभावना।**

अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन यह मजबूरी आवश्यक खर्चों को न करने का कोई तर्क नहीं बन सकती।

पूंजीगत खर्च बढ़ाने की दरकार

हालांकि जीडीपी ग्रोथ की दृष्टि से वर्ष 2015–16 खुशनुमा एहसास देता है, लेकिन यह भी सच है कि पिछले सालों में घरेलू निवेश में लगातार कमी आई है, जिसका बड़ा कारण सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में कमी है। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार सार्वजनिक निवेश को बढ़ाए, सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे आदि क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की खासी गुंजाइश है। मोदी सरकार विदेशी निवेश समेत निजी निवेश को बढ़ाने की कोशिश कर रही है,

सरकार को पूंजीगत खर्च बढ़ाने में भी प्राथमिकता तय करनी होंगी। हम जानते हैं कि उदारीकरण के दौर में सरकार द्वारा कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सभी जरूरी दायित्वों को बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया है। एक समय था जब केन्द्र सरकार के कुल बजट का एक चौथाई से ज्यादा हिस्सा कृषि और ग्रामीण विकास पर खर्च होता था। आज स्थिति यह है कि मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण विकास की परियोजनाओं को अलग कर दिया जाए तो कृषि पर कुल बजट का मात्र 1 प्रतिशत के लगभग ही खर्च होता है। रासायनिक खादों पर सब्सिडी देकर (जो कंपनियों की भेंट चढ़ रही है), सरकार कृषि के प्रति अपने दायित्व की

कि सर्वांगीण कृषि और गांव के विकास के लिए सरकार सक्रिय भूमिका निभाए। कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादकता वृद्वि करने की जरूरत है ताकि किसानों का जीवन स्तर सुधरे। आज गांवों से लोगों को शहरों में लाना संभव नहीं है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ही बेहतर रोजगार और सुविधाओं के निर्माण की जरूरत है। इसमें विदेशी निवेश नहीं आएगा, इसलिए सरकार के खर्च और खासतौर पर सरकारी निवेश की जरूरत है।

स्वास्थ्य न रहे उपेक्षित

एक अन्य क्षेत्र जो उपेक्षित रहा है, वो है स्वास्थ्य का क्षेत्र। सब जानते हैं कि पिछले वर्षों मे न केवल दवाईयों की कीमतें बढ़ी हैं, प्राईवेट अस्पतालों में

ईलाज कराना पहले से कहीं महंगा हो गया है। वर्ष 2014 में जारी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004 और 2014 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल में दाखिल होकर ईलाज कराने की लागत 5695 रूपए से बढ़कर 14935 रूपए हो गई है और शहरी क्षेत्रों में यह लागत 8851 रूपए से बढ़कर 24436 रूपए पहुंच गई है। जाहिर है कि यह खर्च सामान्य गरीब आदमी के बूते के बाहर है, ऐसे में अपने परिजनों के ईलाज और प्राणों की रक्षा के लिए गरीब व्यक्ति अपनी संपत्ति को भी बेच देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर गरीबी के चलते इस कारण भी भूमिहीनता लगातार बढ़ रही है। उदारीकरण के दौर में सरकार स्वास्थ्य सुविधों से अपने हाथ खींच रही है और 2014–15 में केन्द्र सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर खर्च मात्र 31723 करोड़ रूपए था, जबकि वर्ष 2015–16 के लिए इसके लिए प्रावधान में मात्र 1200 करोड़ रूपए की वृद्धि करते हुए उसे 32929 करोड़ रूपए किया गया था। आज देश में सरकारी अस्पतालों की स्थिति को सुधारने की भारी जरूरत है, ताकि गरीब आदमी अपना ईलाज सुविधा से करा सके। यह तभी संभव है कि सरकार स्वास्थ्य पर अपने खर्च को कम से कम दुगुना जरूर करें।

आज देश में डिफ्लेशन का माहौल है और अर्थशास्त्री इस बात से चिंतित है कि वस्तुओं की कीमतें लगातार घट रही है। ऐसे में सरकार यदि अपने खर्च में वृद्धि भी करे, राजकोषीय घाटा थोड़ा बढ़ जाए तो भी सरकार को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, सर्वांगीण कृषि विकास और आमजन के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने से सरकार पीछे न हटे यह समय की मांग है। ❑❑

मार्च तक प्रतिदिन 30 किलोमीटर राजमार्ग का लक्ष्य

केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और नौवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि देश में राजमार्गों के निर्माण में तेजी आई है। मार्च अंत तक प्रतिदिन 30 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण किया जायेगा। उनका कहना है कि उनका लक्ष्य देश में प्रतिदिन 100 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण की क्षमता को विकसित करना है। वर्तमान के 97,000 किलोमीटर से इसका लक्ष्य बढ़ाकर 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में करने का है और इसमें राज्यों से चर्चा करने के बाद इसे 1.75 लाख किलोमीटर तक किया जा सकता है।

नई निर्माणाधीन सड़कों का विवरण देते हुए गडकरी ने कहा कि दिल्ली–जयपुर राजमार्ग पर अधिकतर कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य भी जल्दी ही पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने जानकारी दी कि उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आसान रास्ता बनाने के लिए कार्य जारी है जिसे ऑस्ट्रेलिया से खरीदी गई मशीनों द्वारा पूरा किया जा रहा है। श्री गडकरी के अनुसार उत्तराखण्ड में केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने के क्रम में 900 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है जिस पर 11,700 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और यह कार्य वर्ष 2020 तक पूरा हो जायेगा।

श्री गडकरी ने बताया कि प्लास्टिक के अपशिष्ट से बनी सड़कें, तार रोड निर्माण में 7–8 प्रतिशत तक मिश्रित हो सकती हैं। ठोस अपशिष्ट का प्रयोग दिल्ली और मेरठ के नये राजमार्ग के निर्माण के लिए किया जायेगा। कोलतार सतह के साथ सड़क निर्माण में सीमेंट और कंक्रीट के उपयोग पर बल दिया। राजमार्गों पर लगभग 80 प्रतिशत ट्रैफिक की वृद्धि हुई है। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। 726 अधिक दुर्घटना बहुल क्षेत्रों की पहचान की गई है जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। अगले 5 सालों में 50 प्रतिशत तक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। गडकरी ने परिवहन के लिए इथेनॉल, बायो–डीजल, बायो–सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग करने की जरूरत पर बल दिया। अप्रैल 2020 तक देश में बीएस–VI उत्सर्जन नियम लागू होंगे। उन्होंने जलमार्गों के विकास पर भी बल दिया और कहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015 लोकसभा में पारित हो चुका है उसे आने वाले बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में प्रस्तुत किये जाने की संभावना है। 5 मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्गों सहित राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 हो जायेगी।

श्री गडकरी ने बताया कि कच्छ के कोरी क्रीक से राजस्थान के जालौर में नौवहन नहर के निर्माण के लिए पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन शुरू हो गया है यह मार्च 2016 तक पूरा हो जायेगा। इन्दिरा गांधी नहर के नौगम्य हिस्सों का निर्धारण करने के लिए अध्ध्ययन जारी है। देश में बंदरगाह विकास के प्रोत्साहन के लिए सागरमाला प्रोग्राम को रखा गया है। भारत के समुद्री तट और समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में एक योजना तैयार की जा रही है। बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, मशीनीकरण पर जोर दिया जायेगा। सरकार देश में स्मार्ट बंदरगाहों का निर्माण करने की योजना बना रही है। यहां अपशिष्ट जल को पूरी तरह साफ किया जायेगा। इन स्थानों पर आधुनिक अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी भी खोले जायेंगे। ❑

बैंकों पर भारी दबाव

– अभिजीत लेले –

वित्तीय फंडामेंटल में सुधार और उद्योगों में तेजी की वापसी से लगता है कि आने वाले दिन बेहतर होंगे। लेकिन बैंकों को इस बात से शायद ही सुकून मिल रहा हो। बैंक स्लिपेज को लेकर चिंतित हैं क्योंकि 39 सूचीबद्ध बैंकों की सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) पिछले महीने में बढ़कर 15,000 करोड रुपये से अधिक की हो गई हैं। बैंकरों ने कहा, 'बुरे दिन समाप्त हो चुके हैं और डिफॉल्ट की रफ्तार में कमी आएगी। लेकिन अभी भी अगले एक–दो तिमाहियों तक हम पुनगर्ठित ऋण, छोटी और मझोली कंपनियों और वाणिज्यिक रियल एस्टेट श्रेणी पर अपनी निगाह बनाए रखेंगे।'

इसके अलावा, कृषि ऋण खास तौर से बड़े किसानों (जिनके पास 2 एकड़ से अधिक जमीन है) को दिया गया ऋण कर्ज माफी योजना के तहत आता है और बैंकों के लिए चिंता का यह दूसरा क्षेत्र है। इन किसानों को कुल ऋण के 75 प्रतिशत का भुगतान दिसंबर 2009 तक करन था। शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान सरकार बैंकों को करने वाली थी।

दिसंबर 2009 में समाप्त हुई तीसरी तिमाही में परिसंपत्ति की गुणवत्ता पर दबाव रहा। डिफॉल्ट की रफ्तार में तेजी आई। 39 सूचीबद्ध बैंकों की बकाया गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां तीन महीने में 5,244 करोड रुपये बढ़कर दिसंबर 2009 के अंत में 70,741 करोड़ रुपये हो गई। जुलाई से सितंबर 2009 की तिमाही में 3,911 करोड रुपये के नए एनपीए जुड़े, जो अप्रैल से जून की अवधि के 2,258 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक थे। आर्थिक वृद्धि के माहौल के सुधरने के साथ ही मंदी का प्रभाव घटा है। एनपीए में और बढ़ोत्तरी की रफ्तार क्रमिक तौर पर आने वाली तिमाहियों में घटेगी।

भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष ओ.पी. भट्ट ने कहा कि गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों में सबसे अधिक बढ़ोत्तरी दूसरी तिमाही (2,057 करोड़ रुपये) में हुई। दिसंबर 2009 की तिमाही में इसकी रफ्तार में कमी आई। इस सबसे बड़े ऋणदाता के सकल एनपीए में 1,485 करोड रुपये की बढ़ोत्तरी हुई। आने वाली तिमाहियों में इसमें बढ़ोत्तरी कम होगी।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि पुनर्गठन की गतिविधियों में तेजी आने और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार में अनुमान से कहीं अधिक तेजी आने से बैंकिंग प्रणाली द्वारा रिपोर्ट की गई एनपीए में उस हिसाब से बढ़ोत्तरी शायद ही हो जैसी उम्मीद पहले की जा रही थी। बैंकरों ने बताया कि कुछ पुनर्गठित ऋण अगली तिमाहियों में एनपीए में बदल सकते हैं क्योंकि कंपनियां और अधिक वित्तीय बोझ नहीं सह सकती।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2008 में बैंकों को यह अनुमति दी थी कि वे एक बार किए जाने वाले उपाय के रूप में वैसी कंपनियों को दिए ऋण का पुनर्गठन कर सकते हैं जो बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से नकदी की कमी से जूझ रही हैं। बैंकों की बुक में ऐसे ऋणों को मानक परिसंपत्ति के तौर पर देखा जाना था।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक साल 2009 के मध्य तक बैंकों ने अपने ऋण के लगभग 4.2 प्रतिशत का पुनर्गठन किया। इन मामलों के स्लिपेज से मध्यावधि में बैंकिंग प्रणाली की परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

एसबीआई की बात करें तो इसने 26,794 करोड़ रुपये के ऋण का पुनर्गठन जून 2009 तक किया। इसमें से 996 करोड़ रुपये दिसंबर 2009 तक एनपीए की श्रेणी में आ गिरे। इस प्रकार स्लिपेज अनुपात 5.93 प्रतिशत का रहा। अगर ऋणों की वसूली नहीं हुई तो इन पुनर्गठन के मामलों को सहारों के दूसरे दौर की जरूरत पड सकती है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों को 'सब–स्टैंडर्ड' परिसंपत्तियों के तौर पर देखा जाएगा। स्लिपेज अल्पावधि के लिए होगा।

बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों कहा कि कंपनियों की परेशानियों को गहराई से दूर करने का प्रयास नहीं किया गया है। पुनर्गठन कंपनियों और उनके प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर जल्दबाजी में की गई। ऐसे मामलों में जिन मुद्दों पर विचार नहीं किया गया है वे आने वाली तिमाहियों में सामने आएंगे और बैंकों से दूसरे दौर के सहारे की मांग की जाएगी। ऐसे ऋणों को गैर–निष्पादित ऋण के तौर पर देखा जाएगा। रियल एस्टेट क्षेत्र के छोटे खिलाड़ियों की तरफ से परिसंपत्ति गुणवत्ता की जो चिंता सामने आ रही है इसके बारे में धनलक्ष्मी बैंक के थोक बैंकिंग के प्रमुख राजीव देवड़ास ने कहा कि बाजार में वाणिज्यिक रियल एस्टेट का प्रवाह भारी मात्रा में हो रहा है लेकिन इसकी मांग अभी भी कम है। उन्होंने कहा कि रियल्टी क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी मांग में कमी और संसाधनों के अभाव के प्रबंधन के मामले में सक्षम रहे। लेकिन छोटे खिलाड़ी जिनकी निवेश सीमा सीमा सीमित है और जिन पर बैंकों के कर्ज चुकाने का दबाव है, उनमें जोखिम अधिक है। ❑❑

घटेगा विनिवेश का लक्ष्य!

– अरूप रॉय चौधरी

वित्त मंत्री अरुण जेटली 2016–17 के आम बजट में इस बार ऐसा विनिवेश लक्ष्य रख सकते हैं, जिसे हासिल करना संभव हो सकेगा। माना जा रहा है कि आगामी बजट में विनिवेश के लिए 50,000 से 55,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा जा सकता है, जो चालू वित्त वर्ष के 69,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य से कम होगा। हालांकि इनमें से आधी या करीब 25,000 से 30,000 करोड़ रुपये की राशि घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों में केंद्र की हिस्सेदारी बेचकर जुटाई जा सकती है।

नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष में घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) में रणनीतिक हिस्सेदारी बेचने पर खास जोर दिए जाने की उम्मीद है। बिजनेस स्टैंडर्ड का मानना है कि रणनीतिक शेयर बिक्री की प्रस्तावित प्रणाली के लिए नीतिगत प्रस्ताव को विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही सार्वजनिक किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि इसे बजट से पहले भी जारी किया जा सकता है।

बीमार पीएसयू की रणनीतिक बिक्री या उसे पुनर्जीवित करने के नीतिगत प्रारूप के तहत पूर्व के विनिवेश आयोग की तरह ही एक निकाय का गठन किया जा सकता है, जिसका नेतृत्व कैबिनेट सचिव करेंगे। इस संस्था को यह पता करने की जिम्मेदारी दी जाएगी कि बीमार पीएसयू में सुधार के लिए हिस्सेदारी बेची जाए और नियंत्रण निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपा जा सकता है या फिर उक्त इकाई का विनिवेश करने की जरूरत है। मामले से जुड़े सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए रणनीतिक विनिवेश का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। लेकिन विभिन्न वजहों से इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका। हालांकि अगले वित्त वर्ष के लिए रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री के लिए नीतिगत प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा।'

31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए बजट में 69,500 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 41,000 करोड़ रुपये मुनाफा कमाने वाले सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों में 5 से 15 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर जुटाने की योजना थी और शेष 28,500 करोड़ रुपये बीमार पीएसयू में रणनीतिक विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि बाजार में भारी उतार–चढ़ाव के बीच सरकार विनिवेश के इस लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाई है। अब तक इंडियन ऑयल, डीसीआई, पीएफसी, आरईसी और इंजीनियर्स इंडिया में बिक्री पेशकश के जरिये 13,340 करोड़ रुपये जुटाए जा सके हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इस साल के लिए संशोधित विनिवेश का लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपये के करीब रह सकता है। यह इसलिए भी हो सकता है, क्योंकि बाजार में उतार–चढ़ाव का रुख है और जिन कंपनियों में विनिवेश होना है, उनमें से ज्यादातर तेल और जिंस कारोबार से जुड़ी हैं, जिनमें कोल इंडिया, नालको, एमएमटीसी, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार विनिवेश लक्ष्य में कमी की भरपाई को पूरा करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों से पुनर्खरीद करने को कह सकती है।

नई रणनीतिक व्यवस्था के तहत विनिवेश आयोग की तरह निकाय का गठन किया जा सकता है, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होगी। इस निकाय के गठन का मकसद विनिवेश में अफसरशाही की अड़चनों को दूर करना है। इस निकाय में विनिवेश, सार्वजनिक उपक्रम, आर्थिक मामलों के सचिवों के साथ ही अन्य मंत्रालय के सचिवों को शामिल किया जा सकता है। इस निकाय को समयबद्ध तरीके से रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री करने का काम सौंपा जाएगा। गैर–सूचीबद्ध बीमार पीएसयू के संदर्भ में प्रस्तवित निकाय संबंधित कंपनियों के कारखानों, कार्यालय स्पेस, गोदामों, भूखंडों और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री करने का निर्णय कर सकती है। ❑❑

भारत सरपट दौड़ेगा, ड्रैगन डवाडोल

ड्रैगन (चीन) लड़खड़ा रहा है और भारत दौड़ लगा रहा है। दुनिया भर की निगाहें भारत और चीन पर टिकी हैं कि अगर चीन की अर्थव्यवस्था चौपट हुई तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या भारत तेजी से आगे बढ़ पाएगा या फिर सपनों पर पानी फिर जाएगा? अर्थशास्त्री सिर जोड़कर बैठे हैं, सबके अपने गणित हैं, किन्तु तस्वीर लगभग साफ है, जीतेगा भारत ही।

चीनी अर्थव्यवस्था के किस्से दुनिया भर में चर्चित थे कि कैसे एक देश कुछ ही दशकों में वैश्विक महाशक्ति बन गया लेकिन आज जब चीन की आर्थिक नैया डांवाडोल है तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि ड्रैगन को धराशाई होने में ज्यादा समय नहीं है। यह स्थिति इसलिए बनी, क्योंकि वैश्विक मंदी के चलते दुनिया भर में चीनी उत्पादों की मांग में गिरावट आ रही है। पिछले कुछ सालों से इसके संकेत भी मिल रहे थे। चीनी माल का अधिकांश निर्यात होता था, लेकिन जब वैश्विक मांग में कभी आई तो फैक्ट्रियों में उत्पादन कम हो गया और फैक्ट्रियां घरेलू बाजार पर ध्यान लगाने लगी। इसके अलावा लौह अयस्क, इस्पात, तांबा, कच्चा तेल की भी मांग में कमी चलते चीन को जोरदार झटका लगा है और चीन की अर्थव्यवस्था 25 वर्षों के सबसे निचले पायदान तक फिसल गई है। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि चीनी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आएगी, किन्तु वर्ष 2015 में जिस तरह शंघाई स्टॉक मार्केट धराशाई हुआ, इसके बाद यह भ्रम टूट गया कि चीन एक मजबूत अर्थव्यवस्था है।

चीन में अधिकांश उद्योग एकल स्वामित्व वाले हैं और इन उद्योगों ने बड़े पैमाने पर कर्जा लिया है बाजार में गिरावट आई तो निवेशकों में अपने–अपने स्टॉक को बेचने की आपाधापी मच गई। चीनी सरकार ने जल्दबाजी में स्टॉक बेचने को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। अफवाह फैलाने के आरोप में कारोबारी पत्रकार और न जाने कितने लोग जेलों में ठूंस दिए गए, इसके बाद बाजार में आ रही गिरावट पर कुछ समय के लिए तो रोक लग गई, लेकिन जनवरी में चीनी स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट के बाद सारी दुनिया के बाजारों

चीनी अर्थव्यवस्था पतन के कगार पर है तो भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अगले दो साल तक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर दुनिया में सबसे तेज रहने का अनुमान व्यद्र किया गया है।

– धार्मेन्द्र भदौरिया

पर असर देखा गया। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लाख जतन किए। पिछले साल चीन की मुद्रा युआन का अवमूल्यन किया गया, ताकि निर्यात की स्पर्धा में वह टिका रहे।

चीनी अर्थव्यवस्था पतन के कगार पर है तो भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अगले दो साल तक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर दुनिया में सबसे तेज रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक परिस्थिति एवं परिदृश्य में कहा गया है कि वर्ष 2016 में भारत की विकास दर 7.3 प्रतिशत तथा 2017 में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि 2015 में यह 7.2 प्रतिशत रही। हालांकि आईएमएफ ने 2016 और 2017 में इसके 7.5 प्रतिशत ही रहने का अनुमान व्यक्त किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेल, धातु और खाद्यान्नों की कीमतों में गिरावट के चलते देश के आर्थिक हालात में सुधार आया है। रिपोर्ट में इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2.9 प्रतिशत तथा अगले साल 3.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान बताया है, जबकि दक्षिण एशिया का विकास अनुमान 2016 में 6.7 प्रतिशत तथा 2017 में सात फीसदी रखा गया है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान सबसे अधिक होगा। भारत की दक्षिण एशियाई

सस्ते उत्पाद आएंगे तो निर्यात भी बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा भी आएगी, लेकिन हमें विदेशी मुद्रा का मोह कुछ हद तक कम करना होगा। देश का विकास, देश की पूंजी से ही होगा।

अर्थव्यवस्था में 70 प्रतिशत की भागीदारी है। उधर वाणिज्य और उद्योग संगठन एवं बिजकॉन की संयुक्त सर्वे में शामिल कंपनियों और लोगों में से 63 फीसदी का मानना है कि अगले छह महीनों में देश की अर्थव्यवस्था की हालत और सुधरेगी, हालांकि वैश्विक माहौल के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रभावित हुआ है, किन्तु निर्माण बुनियादी ढांचा एवं विनिर्माण के क्षेत्र में भारी निवेश कर रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। हम दुनिया की 16 फीसदी जनसंख्या है लेकिन वैश्विक मैन्यू–फैक्चरिंग में हमारी भागीदारी मात्र 2.04 प्रतिशत है, जबकि चीन की 23 फीसदी थी और वैश्विक मैन्यू–फैक्चरिंग में नंबर एक पर था। 1991 में चीन भी 2.4 प्रतिशत पर था। अमेरिका 17.5 प्रतिशत के साथ नंबर दो पर है। हमारी जो 2.04 प्रतिशत की भागीदारी है, उसमें भी भारतीय उद्यमों और उत्पादों की भागीदारी एक तिहाई से भी कम है। अनेक उद्योग विदेशी ब्राण्डों के लिए उत्पादन करते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के पास ज्यादा खोने के लिए क्या है? अगर दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही है तो इसका फायदा किसे मिलेगा? मोटी–मोटी बात है, इसका नुक्सान उन देशों को होगा जो तेल उत्पादक हैं, हालांकि असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत का निर्यात इन्हीं देशों मध्यपूर्व में होता है, लेकिन वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग में जब हमारी भागीदारी ही न के बराबर है तो हम पर कितनी मार पड़ेगी? आंकड़े आए हैं कि पिछले साल की तुलना में निर्यात 16 फीसदी कम हुए हैं। बाजार में जब मांग ही नहीं है, तो निर्यात तो घटेंगे ही, किन्तु ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि हमारे देश में उद्यमशीलता बढ़ रही है। सस्ते उत्पाद आएंगे तो निर्यात भी बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा भी आएगी, लेकिन हमें विदेशी मुद्रा का मोह कुछ हद तक कम करना होगा। देश का विकास, देश की पूंजी से ही होगा।

हालांकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर है और अगर एक अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है तो इसका असर दूसरी पर भी पड़ता है लेकिन भारत का मामला जरा अलग है। हम पर असर तो पड़ता है, लेकिन जोर का झटका धीरे से लगता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई थी, तब भी हम पर इतना असर नहीं हुआ था, जितना कयास लगाए जा रहे थे। देश में भरोसे का जो माहौल बना है, वह हमारे लिए शुभ संकेत है। दूसरे देशों की तरह हम न अमेरिका पर ज्यादा निर्भर थे और न ही चीन पर। छोटा–मोटा झटका तो हमें भी लगेगा, लेकिन हम उससे जल्दी ही उबर जाएंगे, क्योंकि भारत का अर्थतंत्र दुनिया भर से हटकर है। हम चार्वाक के नहीं उस दर्शन के अनुयायी हैं, जिससे कहा गया है, *'उतने पैर पसारिये जितनी लंबी सौर'*। ❑❑

प्रकृति व पर्यावरण के प्रति असहिष्णुता घातक

कृषि में जैविक आदायों के स्थान पर रसायनों के असंतुलित व अनियंत्रित उपयोग से कई प्रदेशों में भूमि व्यापक स्तर पर बंजर हुयी है और प्रकृति में स्व-संचालित जैविक उर्वरता-सवंर्द्धन व कीट नियंत्रण में सहयोगी कीट व सूक्ष्मजीवी कम होते चले गये हैं।

- प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

आधुनिक विज्ञान द्वारा कृषि, बागवानी व पशुपालन के क्षेत्र में विकसित कई नव्य तकनीकों व पद्धतियों से आज पर्यावरण, पारिस्थितिकी व जन–स्वास्थ्य के लिये कई गंभीर संकट उत्पन्न हो रहे हैं। अतएवं इन नव्य तकनीकों के व्यावहारिक उपयोग के पूर्व, जन–स्वास्थ्य व पारिस्थितिकी पर होने वाले उनके प्रभावों की समीक्षा भी आवश्यक हो जाती है। कृषि में जैविक आदायों के स्थान पर रसायनों के असंतुलित व अनियंत्रित उपयोग से कई प्रदेशों में भूमि व्यापक स्तर पर बंजर हुयी है और प्रकृति में स्व–संचालित जैविक उर्वरता–सवंर्द्धन व कीट नियंत्रण में सहयोगी कीट व सूक्ष्मजीवी कम होते चले गये हैं। देशी नस्ल के गौ–वंश के विदेशी संकर नस्लों में रूपांतरण के कारण, अब ये नयी संकर प्रजातियाँ, A_2 श्रेणी के स्वास्थ्यवर्द्धक दूध के स्थान पर A_1 श्रेणी का ऐसा दूध दे रही हैं, जिससे मधुमेह, स्वलीनता का मनोविकार (ऑटिज्म), साइजोफ्रेनिया स्थायी अपचन व हृदय रोग सहित कई रोग महामारी के स्तर पर बढ़ रहे हैं। गौ–वंश के साथ किये इन अनुप्रयोगों की तरह अब ऐसे ही घातक प्रयोग देश में विदेशी कंपनियों के लिए 6–7 लाख करोड़ का बीजों का कारोबार स्थापित करने के लिये जी.एम. (जेनेट्रिकली मॉडीफाइड) फसलों के प्रसार के प्रयासों से किये जा रहे है। ये सभी जी.एम. फसलें जन–स्वास्थ्य के लिये अत्यंत असुरक्षित एवं पर्यावरण, देश कृषि जैव–द्रव्य (जर्म प्लाज्म) की शुद्धता व पूरे देश की जैव विविधता के लिये अत्यंत खतरनाक हैं। देश में कृषि की महत्ता व उस पर बिना विचारे अपनायी जा रही तकनीकें कितना घातक प्रभाव डालनी वाली है, यह बात अग्रलिखित विवेचन से स्पष्ट हो जाती है।

भारत–कृषि महाशक्तिः विश्व की सर्वाधिक 16 करोड़ हेक्टर कृषि योग्य भूमि व सर्वाधिक 5.9 करोड़ हेक्टर सिंचित क्षेत्रफल भूमि केवल भारत के पास है। प्रतिवर्ष जो 20 करोड़ हेक्टर मीटर जल वर्षा ऋतु में बिना उपयोग के समुद्र में चला जाता है, उसके उपयोग से देश के समस्त कृषि योग्य 16 करोड़ हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई संभव है। ऐसा होने पर भारत विश्व की दो तिहाई जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति कर सकता है और विश्व कृषि महाशक्ति का स्थान ले सकता है।

रसायन प्रधानता से बंजर होती भूमिः स्वाधीनता के बाद विशेषकर 70 के दशक से जैविक खाद व अन्य आदायों के स्थान पर रासायनिक खाद व संदिग्ध कीटनाशकों को प्रोत्साहन देते चले जाने व उसमें भी विविध पोषक तत्वों पर असंतुलित अनुपात में अनुदान दिये जाने से नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश में भारी विषम–अनुपात, जिसके अंतर्गत अत्यधिक नाइट्रोजन (यूरिया) उपयोग के कारण भूमि बड़ी मात्रा में ऊसर व अन–उर्वरा होती चली गयी है। हाल ही में आये संसदीय समिति के एक प्रतिवेदन में कहा गया है कि पंजाब में एन.पी.के. के अनुपात की विषमता 39:9:1 पर पहुंच गयी है, इसका राष्ट्रीय औसत भी 7:3:1 पर चला गया है, जबकि आदर्श अनुपात 4:2:1 है। इसलिये प्रति किलो एन.पी.के. से जहां 1970 में 50 किलो अनाज की उपज मिलती थी, वह घटकर 10 किलो रह गयी है।

पूरे देश में ही पोटाश, यशद (जिंक) व अन्य सूक्ष्म पोषकों एवं भूमि की उर्वरता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं के अभाव में भूमि की उर्वरता में भारी कमी आयी है और उसे बढ़ाने के लिये किसान द्वारा अधिकाधिक यूरिया के उपयोग से भूमि बंजर होती जा रही है।

दूसरी ओर नीदरलैंड्स (हॉलेण्ड) में जैविक खाद के उपयोग–वश वहां पर फसलों की उत्पादकता भारत की तुलना में 4–5 गुनी है। अपने देश में कीटनाशकों के भी अनियंत्रित उपयोग के कारण मृदा व बाहरी परिवेश में पाये जाने वाले फसलों के मित्र कीट व जीवाणुओं के विनष्ट हो जाने से मृदा की उर्वरता में वृद्धिकर्त्ता केंचुए व ऐसे ही अन्य सभी विविध जीवाणु ही समाप्त होते चले गये है एवं जैविक कीट नियंत्रण में सक्षम फसलों मित्र कहे जाने वाले कीट व सूक्ष्म जीवाणु भी पूरी तरह समाप्त हो गये हैं। उदाहरणतः नियो निकोटिनाइड श्रेणी के कीटनाशक मधुक्खियों में स्मृति–लोप से उन्हें विनष्ट कर रहे हैं, जो अनेक फसलों में क्रास पालिनेशन से उनकी उत्पादकता बनाये रखती हैं। वहीं एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग कीटनाशी मनुष्यों की अन्तःस्त्रावी ग्रंथियों को प्रभावित कर संपूर्ण स्वास्थ्य के लिये चुनौती सिद्ध हो रहे हैं। इन दोनों ही श्रेणी के कीटनशाकों को यूरोप में प्रतिबंधित करने के बाद अब देश में इनके परीक्षण प्रारंभ कर दिये है। कीटनाशकों के अति उपयोग के कारण तो आज भूगर्भ का जल तक भी प्रदूषित होने लग गया है। कोकाकोला में पाये पेस्टीसाइड के अवशेष उसी का परिणाम है।

बाहरी परिवेश में पाये जाने वाले फसलों के मित्र कीट व जीवाणुओं के विनष्ट हो जाने से मृदा की उर्वरता में वृद्धिकर्त्ता केंचुए व ऐसे ही अन्य सभी विविध जीवाणु ही समाप्त होते चले गये है

विदेशी संकर गौ–वंश का दूध बढ़ते मधुमेह, हृदय रोग व मनोविकारों का कारणः इसी प्रकार देश के गौ–वंश को विदेशी प्रजातियों की नस्ल से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा जर्सी, हॉल्स्टीन आदि संकर नस्लों में बदल देने से अब देश की ये अधिकांश संकर नस्लें A_1 श्रेणी का रोग–कारक दूध देने लग गयी हैं। हमारी गायों की सभी पारंपरिक देशी नस्लें सहस्त्राब्दियों से A_2 श्रेणी का ही दूध देती रही हैं। वस्तुतः A_2 व A_1 श्रेणी दूध के प्रोटीन (केसीनो प्रोटीन) के 208 अमीनो एसिड्स में केवल एक अमीनो एसिड के अंतर से वह टाइप 1 की डायबिटीज, हृदय रोग, स्थायी अपचन, मस्तिष्क विकार यथा स्वलीनता (ऑटिज्म) व साइजोफ्रेनिया (मनोच्छेद –एक मनोरोग) जैसी कई बीमारियां उत्पंन करता है। दूसरी ओर गायों की भारतीय नस्लों द्वारा एक भिन्न अमीनों एसिड युक्त केसीनो–प्रोटीन वाला A_2 श्रेणी का दूध दिया जाता है। यह भारतीय नस्लों का A_2 दूध मनुष्य को मधुमेह से बचाता है, हृदय की धमनियों में अवरोध नहीं होने देता है अर्थात हृदय रोग से बचाता है और बच्चों के मस्तिष्क के बेहतर विकास में सहायक होता है। भारतीय नस्ल का A_2 दुग्ध हृदय रोग से बचाव करने वाला होने से ही आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक–संहिता में हृदय रोग के उपचार में गौ–घृत का उपयोग निर्देशित है। विदेशी नस्ल व उनकी संकर प्रजातियों का A_1 दूध तो बाल्यकाल में ही टाइप 1 की डाइबिटीज उत्पन्न करने के साथ ही हृदय की धमनियां अवरोध और बच्चों के मस्तिष्क में अनेक विकारों को जन्म देता है।

दुर्भाग्य से हमने तो भारत में अधिकांश शुद्ध देशी नस्लों को विदेशी हॉल्स्टीन आदि की संकर नस्लों में बदल कर अनेक महामारियों को आमंत्रण ही दे दिया है। विश्व में अब केवल ब्राजील नामक देश आज A_2 दूध की शुद्ध भारतीय नस्लों को संजोये हुये है और भारतीय नस्लों व भारतीय नस्लों के गौ–वंश के वीर्य का भी आज सबसे बड़ा निर्यातक है। आज जब अमेरिका व यूरोप सहित विश्व के सभी देशों में A_2 दूध के बढ़ते चलन से उसकी माँग बढ़ रही है और A_2 दूध की उत्पादक व विपणनकर्त्ता कंपनियाँ अपनी दूध की थैली पर A_2 दूध भी लिखती है। हमारे

द्वारा भी अपने गौ–वंश की नस्ल रूपांतरित कर देने से अब भारत विश्व में मधुमेह, हृदय रोग व मनोविकारों की राजधानी न बन जाये इसके लिये अब भारतीय गौ–वंश की शुद्धता लौटाने हेतु ब्राजील का सहारा लेना पड़ सकता है।

जी.एम. फसलों के भयावह खतरे: देश में जैव रूपांतरित फसलों अर्थात् जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) फसलों के परीक्षण के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका विचाराधीन होने पर भी पूर्व पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोयली ने तो फरवरी 2014 के अन्त में इनके परीक्षण की अनुमति देकर देश में जन–स्वास्थ्य व हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संमुख एक गंभीर संकट ही उत्पन्न कर दिया है। न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने के स्थान पर परीक्षणों को अनुमति दे देने के पीछे ऐसी फसलों से अरबों रुपये के कारोबार के लिये लालायित विदेशी कंपनियों के दबाव का प्रभाव होना भी स्वाभाविक है। मोयली के जाने के बाद भी देश 'आनुवांशिकीय अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति' द्वारा ओर भी अधिक प्रजातियों के अनुमोदन कर निर्णय अत्यंत चिंताप्रद है।

वस्तुतः किसी फसल में किसी भी अन्य जीव में विद्यमान कोई इच्छित गुण प्रकट करने के लिये, उस वांछित गुण से युक्त भिन्न पौधे या जन्तु के उस वांछित गुण के कारक 'वंशाणु' या 'जीन' (Gene) को प्रत्यारोपित करने पर उस बाहरी वंशाणु से युक्त नयी फसल की प्रजाति को 'जैव–रूपांतरित' या 'जी.एम.' अर्थात् जेनेटिकली मॉडीफाइड फसल कहते है। उदाहरण के लिये टमाटर को पाले से बचाने के लिये टमाटर की फसल में बर्फीले समुद्र में पायी जाने वाली मछली में विद्यमान (उसे बर्फ की ठंडक से बचाने वाली उस) जीन (Gene) या वंशाणु को प्रत्यारोपित करके पाला रोधी (फ्रोस्ट रेजिस्टेण्ट) टमाटर विकसित किया जा सकता है। इसी प्रकार कपास पर लगने वाले डोडा कीट (ball-worm) को मारने में सक्षम विष उत्पादक बैक्टीरिया 'बेसिलस थोरेंजियेंसिस' में उपलब्ध इस विष के जनक वंशाणु या जीन को कपास में प्रत्यारोपित करके ऐसा बी. टी. कपास विकसित किया गया है जिससे उस कपास में उस डोडा कीट को मारने की आंशिक सामर्थ्य आ जाती है। लेकिन उससे अब वह डोडा कीट ऐसे 'सुपर कीट' में संवर्द्धित हो रहा है कि वह अब बी.टी. कपास के उस विष को भी सह लेता है। अब तो पंजाब में उसी कीट रोधी (Pest-resitant) बी. टी. कपास पर हाल ही में हुआ सुपर पेस्ट रूपी व्हाइट फ्लाई का प्रकोप अत्यंत घातक सिद्ध हुआ है अथवा संभवतः उस बी.टी. कपास प्रजाति में बाहरी जीन के प्रवेश से आये अनुवांशिकीय परिवर्तन जनित भी हो सकता है जिसमें उस कपास की रोग प्रतिरोधकता कम हुयी हो। अब हाल में ऐसी कीटरोधी या खरपतवारनाशक रोधी विशेषताओं से युक्त सैकड़ों जैव रूपांतरित फसल प्रजातियां मक्का, सरसों, कपास, बैंगन, सोयाबीन, अरण्डी, चावल, गेहूं आदि की तैयार की गयी हैं। पर्यावरण मंत्री वीरप्पा मोयली द्वारा हाल ही में फरवरी 28 को 'अनुवांशिकीय अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति' द्वारा अनुमोदित जिन फसल प्रजातियों के परीक्षण की छूट दी गयी है, वे 200 से अधिक है। इतनी बड़ी संख्या में जी. एम. फसल प्रजातियों का खुले में परीक्षण किये जाने पर इन फसलों के परीक्षण की अवधि में आस–पास के वानस्पतिक जगत के जैव द्रव्य के प्रदूषण की प्रबल संभावनायें बन गयी है। ऐसे परीक्षण ग्रीन हाउस में ही किये जाने चाहिये जिससे इनके पराग कण जैविक प्रदूषण नहीं फैला सके।

वस्तुतः खुले खेतों में इन जैव रूपांतरित (जी.एम.) फसलों के परीक्षण की दशा में इन फसलों के पराग कणों का विकीरण हवा से या मधुमक्खियों के साथ चिपक कर 2–3 किलोमीटर क्षेत्र में हो जाने पर वे पराग कण (Polkn grains) आस–पास की साधारण फसलों या अन्य पादप प्रजातियों का परा–परागण (क्रास पालिनेशन) कर सकते है। ऐसे में इन स्थानीय प्रजातियों के पुष्पों का परा–निषेचन (Cross fertilisation) इन जी.एम. फसलों के पराग कणों (Pollens) से हो जाने पर ये बाहरी वंशाणु या जीन उन फसलों या पादपों के जैव द्रव्यों को अनजाने में ही प्रदूषित कर सकते है। ऐसा परा–परागण या परा–निषेचन वनस्पति जगत में सामान्यतया नहीं, लेकिन अपवाद स्वरूप हो जाना असंभव नहीं है। वरन्, ऐसा होता भी रहा है। इस प्रकार पर–परागण या परा–निषेचन की संभावना को निर्मूल करने हेतु ही जी. एम. फसलों में टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी अर्थात बाँझ बीजों का उपयोग सुझाते है। ऐसा करने से इन पौधों के पराग

न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने के स्थान पर परीक्षणों को अनुमति दे देने के पीछे ऐसी फसलों से अरबों रुपये के कारोबार के लिये लालायित विदेशी कंपनियों के दबाव का प्रभाव होना भी स्वाभाविक है।

कण नपुंसक हो जाते है, जिनसे निषेचन या परा–निषेचन ही संभव नहीं हो सकता है। लेकिन, भारत में टर्मिनेटर या बाँझ बीजों का उपयोग नहीं सुझाया जा सकता है। क्योंकि, तब किसानों को उनकी फसल से बीज नहीं प्राप्त हो सकेगा और प्रतिवर्ष वे महंगा बीज खरीदने में सक्षम नहीं है। इसलिये ऐसे में किसान हर बार महंगे बीज खरीदने को विवश होने पर ऐसे महंगे बीजों के बदले विदेशी कंपनियों के लिये अनुबंध पर खेती करने को बाध्य होंगे।

परीक्षण के बाद इन फसलों की खेती की दशा में भी जैव रूपांतरित फसलों में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की संभावनायें भी बनी रहती है। इन फसलों में संभवतः हजारों वर्षों में भी उत्परिवर्तन नहीं हो और यह भी संभव है कि वर्ष–दो वर्ष में या कभी भी कोई भी अच्छा या बुरा उत्परिवर्तन हो सकता है। उत्परिवर्तन की दशा में ही वह फसल अधिक गुणकारी या एलर्जी पैदा करने वाली अथवा विषैली हो सकती है। इस प्रकार का उत्परिवर्तन कब होगा तथा कैसा होगा या नहीं होगा, इसका कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। गायों की विदेशी नस्लें भी पूर्व में स्वास्थ्यवर्द्धक A_2 दूध ही देती थी। लेकिन उनमें कब म्यूटेशन हुआ व कब से वे रोगकारी दूध देने लग गयी; यह पता भी हमें बहुत बाद में चला देशी व विदेशी नस्लों के दूध में A_2 व A_1 का यह अंतर भी म्यूटेशन का ही परिणाम है।

परीक्षणों के बाद व्यापारिक स्तर पर जी.एम. फसलों को इन्हें उगाने पर ये खाद्य कितने खतरनाक हो सकते है, इसके भी कुछ उदाहरणों व प्रयोगों का उल्लेख यहां आवश्यक है। अनेक प्रयोगों में जी.एम. टमाटर का आहार चूहों को देने से उनके आमाशय में रक्तस्राव, बी. टी. आलू से चूहों में आंत्रक्षति, बी.टी. मक्का से सूअरों व गायों में वन्ध्यापन, आर.आर. सोयाबीन से चूहों, खरगोशों आदि के यकृत, अग्न्याशय आदि पर दुष्प्रभाव आदि के अनेक मामले प्रायोगिक परीक्षणों के सामने आये है। जी.एम. फसलों से व्यक्ति में एंटीबायोटिक दवाओं के विरूद्ध प्रतिरोध उपजना, कोशिका चयापचय (सेल मेटाबालिज्म) पर प्रतिकूल प्रभाव आदि जैसी अनेक जटिलताओं के भी कई शोध परिणाम सामने आये है। बी.टी. कपास की चराई के बाद कुछ भेड़ों के मरने आदि के भी समाचार आते रहे है। जी.एम. फसलों या खाद्य के अनगिनत दुष्प्रभावों के परिणाम प्रयोगों में सामने आते रहे है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि एवेण्टिस कंपनी की स्टार लिंक नामक जी.एम. मक्का खाने से जापान व कोरिया में एलर्जी की समस्या उत्पन्न हुयी थी। उसी मक्का को अमरीका में एक खाद्य उत्पादक क्राफ्ट बेल नामक कंपनी को बेच देने पर क्राफ्ट बल कंपनी को उस जी.एम. मक्का से बने टेक्नो–शेल नष्ट करने पड़े थे एवं उस एक ही मामले में एवेण्टिस को छः करोड़ डालर (आज की विनिमय दर पर लगभग रु. 400 करोड़ तुल्य) की क्षतिपूर्ति का भुगतान वर्ष 2000 में करना पड़ा था। अब जी.एम. मक्का को पशुओं को ही खिलाया जाता है।

हाल ही में नवंबर 12, 2012 को आस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने 'फ्रेन्केन' नाम जैव रूपांतरित गेहूं के बारे में चेतावनी देते हुये कहा है कि इस गेहूं से यकृत खराब (लीवर फैल्यर) हो सकता है। पागलपन या खाने वाले की अनुवांशिकी पर भी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। इस गेहूं में बाहरी वंशाणु (जीन) प्रवेश कराने के स्थान पर इसी के कुछ वंशाणु अवरूद्ध (जीन ब्लाक) किये गये है।

जी.एम. फसलों के उपरोक्त प्रत्यक्ष दुष्प्रभावों के अतिरिक्त देश में प्रत्येक फसल की प्रजातियों में जो अथाह विविधता है और जिसके कारण प्रत्येक प्रजाति में प्रकृति में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के विरुद्ध प्रतिरोध की भिन्न–भिन्न प्रकार की विविधतापूर्ण सामर्थ्य है। उनके स्थान पर एक ही जी.एम. फसल लेने पर हमारी विविध वैशिष्ठ्य वाली जैविक निधि भी विलोपित हो जायेगी। इसके अतिरिक्त पराग कण विकीरण की संभावनाओं के चलते क्या इनके खुले परीक्षण के लिये भी कदम बढ़ाने चाहिये? एक बार किसी देश की कृषि एवं उसकी कृषि फसलों सहित संपूर्ण वानस्पतिक जगत के जैव द्रव्य के प्रदूषण से होने वाली क्षति की पूर्ति क्या कभी भी संभव हो सकेगी? अतएवं अब देश की कृषि, कृषि उत्पादों की शुद्धता, जन–स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण के लिये निम्नांकित उपाय आवश्यक हैं।

जैविक व प्राकृतिक कृषि– एकमेव श्रेयस्कर मार्गः अब हमें पुनः जैविक कृषि व प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ना चाहिये इस हेतु निम्नांकित करणीय कार्य हैं–

1. समाज में रसायन प्रधान कृषि, विदेशी नस्ल के गौ–वंश के A_1 श्रेणी के रोग–कारक दूध और जी. एम. फसलों के दुष्प्रभावों की जानकारी कराना।
2. जैविक कृषि को अपनाने के साथ ही ऐसे जैविक कृषि उत्पादों के विपणन की (Marketing) प्रभावी व्यवस्था करना। देश में खुले में चल रहे सभी प्रकार के जी.एम. फसलों के परीक्षणों पर रोक लगाना।
3. विदेशी संकर नस्लों के रोगकारी A_1 दुध के स्थान पर शुद्ध देशी नस्ल के स्वास्थ्यवर्द्धक A_2 श्रेणी और दुग्ध उत्पादों के विपणन के लिए सभी प्रयास करना।
4. सभी प्रकार के स्थानीय बीजों, जीव प्रजातियों और देशी–गाय सहित सभी देशी नस्लों के पशुधन के संवर्द्धन एवं उनके उत्पादों के विपणन व प्रवर्तन के लिए प्रयास करना। ❑❑

नहीं चलेगा अब ढुलमुल रवैया

पिछला साल ऐसी घटनाओं का रहा जो एक दूसरे से संबंधित होने के साथ हमारे भविष्य की गंभीर तस्वीर प्रदर्शित करती है। अब हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दिसंबर में पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का समापन ऐसे समझौते के साथ हुआ जो महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और समानता के धरातल से दूर प्रतीत होता है। उसके बाद चेन्नई त्रासदी देखने को मिली। इससे यह सबक भी मिला कि यदि हम इसी तरह कुप्रबंधन करते रहे तो अति मौसमी दशाओं का शिकार हमको होना पड़ेगा। उसके बाद दिल्ली में जहरीली हवा के असर और सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा के संकट का मसला देखने को मिला। उससे यह सबक मिला कि यदि आप सांस लेने लायक हवा चाहते हैं तो कम से कम एक साथ तकनीक और परिवहन के लिहाज से बदलती जीवन शैली की प्रवृत्तियों के सम्मिलन को अपनाना होगा। इन घटनाओं से कुछ सख्त संदेश निकले। पहला, यदि हम सुरक्षित जीवन और स्वास्थ्य चाहते हैं तो पर्यावरणीय मसलों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा, विकास के मौजूदा मॉडल के विपरीत प्रभावों के मद्देनजर हमें इसके लिए दूसरे रास्तों को अपनाना होगा। तीसरा, हमारा ग्रह लगातार गरम हो रहा है इसलिए जो भी करना है उसे आवश्यकता से अधिक तेज गति से करना होगा।

जलवायु परिवर्तन से संबंधित इन अति मौसमी दशाओं को हम पहले ही देख रहे हैं और इनके असर से पिछले साल फसलों के खराब होने से देश के लाखों किसानों का जीविकोपार्जन प्रभावित हुआ है। कमजोर नीतियों और असामयिक मौसमी दशाओं की मार से किसान मानसिक अवसाद के शिकार होकर आत्महत्या तक कर रहे हैं।

– सुनीता नारायण

पेरिस समझौते को एक लक्षण के रूप में देखना चाहिए। दुनिया आज दो आपदाओं के बीच घूम रही है। एक, हमारी आर्थिक विकास की जरूरत और दूसरी अंधाधुंध अत्यधिक उपभोग जिसके चलते वायुमंडल में जहरीली ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। प्राथमिक रूप से हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए इन गैसों के उत्सर्जन ने हमारे भविष्य को दांव पर लगा दिया है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित इन अति मौसमी दशाओं को हम पहले ही देख रहे हैं और इनके असर से पिछले साल फसलों के खराब होने से देश के लाखों किसानों का जीविकोपार्जन प्रभावित हुआ है। कमजोर नीतियों और असामयिक मौसमी दशाओं की मार से किसान मानसिक अवसाद के शिकार होकर आत्महत्या तक कर रहे हैं। इन सबके चलते विकास के लाभ से महरूम हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं पेरिस समझौते की कमजोर भाषा ने हमको दीनहीन ढंग से विफल किया है। उसमें पहले से समृद्ध और संपन्नता की ओर अग्रसर देशों ने संकेत दिया है कि अपनी आर्थिक वृद्धि या उपभोग के मामले में बाकियों के हितों के मद्देनजर वे समझौता नहीं करने वाले हैं। दूसरी त्रासदी हमें असमान, असुरक्षित और असहिष्णु विश्व में रहने के लिए मजबूर करने वाली है। पेरिस समझौता हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि अमीर जगत ने जो अपना बुलबुला बनाया है उसमें उनको यकीन है कि न ही उसे कोई पकड़ या फोड़ सकता है। इस बुलबुले में सुरक्षित रहने के लिए बातचीत केवल उन्हीं विषयों तक सीमित है जो अधिक सुविधाजनक है। नतीजतन जलवायु परिवर्तन से लेकर व्यापार और अंतरराष्ट्रीय समझौतों में एक प्रभावी पक्ष रहता है। सबसे शक्तिशाली मुल्क यह यकीन करते दिखते हैं कि दूसरी तरफ या पक्ष में कोई नहीं है। इसलिए दूसरे की पोजीशन का कोई सम्मान नहीं है। यह मान लिया गया है कि दूसरा पक्ष या तो आतंकी या कम्युनिस्ट या भ्रष्ट या अक्षम है। इसलिए भिन्न विचारों, दृष्टिकोणों और वास्तविकताओं को खारिज किया जा रहा है।

इन सबके बीच विश्व में असमानता बढ़ रही है। आर्थिक वृद्धि और संपन्नता की कोई भी मात्रा अब पर्याप्त नहीं है क्योंकि आकांक्षा ही नया ईश्वर है। ऐसे में जो भी गरीब होगा वो सीमांत या हाशिए पर होगा। इस नए साहसी विश्व में ऐसे विफल लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत पर आधारित है। इन सबसे भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। इसकी परिणति हिंसक युद्ध की होगी। लेकिन हमको इसे अभी और सदा के लिए बदलना होगा। हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। ❑❑

(लेखिका डायरेक्टर जनरल, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट हैं।)

भारत को नहीं चाहिए जीएम सरसों

जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों के लिए वाणिज्यिक अनुमोदन स्थगित करने के 13 सालों बाद यह जिन्न एक बार फिर से वापस आ गया है। करदाताओं की गाढ़ी कमाई के लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत वाली जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती इस बार सार्वजनिक उपक्रम का भेष धर कर मंजूरी के लिए आई है। जबकि इतनी राशि से 3 हजार से अधिक नए स्कूल आरंभ किए जा सकते हैं।

दावा भी वहीं है, भाषा भी वहीं है (लगभग एक ही है) और हमारी आशंका भी वहीं है। इससे पहले कृषि–रसायन की दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनी बायर की सह संस्था, प्रो–एग्रो सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया था कि उसकी जीएम सरसों चार विदेशी जीन से युक्त है और यह सरसों का उत्पायदन 20 से 25 फीसदी तक बढ़ा देगी। इस जीएम सरसों से तेल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। अब नई दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर मेनिपुलेशन ऑफ क्राप प्लांट्स ने नए जीएम सरसों को विकसित कर दावा किया है कि इसमें तीन–तीन विदेशी जीन हैं – बार, बारनेस और बारस्टार। सेंटर भी अपनी फसल को लेकर प्रो–एग्रो सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ही तरह दावा कर रहा है। साथ ही जीएम सरसों के दोनों पैरोकार प्रो–एग्रो सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अब दिल्ली विश्वविद्यालय नई जीएम सरसों में खरपतवार प्रतिरोध होने की बात से इंकार कर रहे हैं हालांकि दोनों ही ने इस कार्य के लिए ज्ञात जीन का उपयोग किया है।

भारत प्रतिवर्ष 60 हजार करोड़ के खाद्य तेलों का आयात कर रहा है और इसलिए तत्काल सरसों के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्ययकता है जिसका अर्थ हुआ कि अधिक खाद्य तेल का उत्पाादन विदेशी मुद्रा की बचत होगी। मैंने कई पैनल चर्चाओं और इस विषय पर सार्वजनिक बहस में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक पूर्व कुलपति और नई जीएम सरसों

भारत प्रतिवर्ष 60 हजार करोड़ के खाद्य तेलों का आयात कर रहा है और इसलिए तत्काल सरसों के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्ययकता है जिसका अर्थ हुआ कि अधिक खाद्य तेल का उत्पाादन विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
– देवेन्द्र शर्मा

को विकसित करने वाले डॉ दीपक पेंटल को बार–बार यह कहते हुए सुना है कि खाद्य तेल के आयात में खर्च की जा रही विदेशी मुद्रा में कटौती करने की आवश्यतकता है। यह बचत भारत जैसे विकासशील देश के लिए बड़ी बचत होगी। यह वही बात है जो 13 साल पहले प्रो एग्रो द्वारा विकसित जीएम सरसों के पैरोकारों द्वारा बार–बार कही जाती थी। उस समय यानी 13 साल पहले घरेलू आवश्यकता का करीब 50 प्रतिशत खाद्य तेल आयात किया जाता था और इस आयात पर सरकार लगभग 12 हजार करोड़ रुपए खर्च करती थी।

कोई भी शिक्षित व्यक्ति इस तर्क का समर्थन ही करेगा कि खाद्य तेल के आयात पर खर्च होने वाली भारी राशि में कटौती होनी चाहिए। लेकिन जीएम सरसों की पैरवी करने वाली लॉबी बहुत चतुराई से यह बात छुपा जाती है कि कि केवल सरसों के कम उत्पादन के कारण ही खाद्य तेल के आयात पर इतनी राशि खर्च नहीं करनी पड़ रही है। वास्तव में ऐसा नहीं है। इतनी अधिक मात्रा में तेल आयात के कई और कारण भी हैं। लेकिन वे तो केवल जीएम सरसों के उत्पादन की कमी को रेखांकित कर जीएम सरसों को बाजार में लाना चाहते हैं।

अतीत में देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत में आयात की वृद्धि से खफा थे। वे मैक्रो–अर्थशास्त्रियों चालू खाते के घाटे में रूप में परिभाषित इस खर्च में कटौती करने के लिए बेताब थे। यदि आयात की जाने वाली सामग्री की सूची बनाएं तो ईंधन, उर्वरक और खाद्य तेल इस सूची में सबसे ऊपर होंगे। उस समय खाद्य तेलों का वार्षिक आयात बिल 1500 से 3000 हजार करोड़ रुपए के आस–पास था। इस बात को समझते हुए कि भारत में तिलहन उत्पादन में बढ़ोतरी और प्रसंस्करण क्षमता है और उत्पादन बढ़ाकर तेल आयात के इस बड़े खर्च में कटौती की जा सकती है राजीव गांधी ने भारत में घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए 1985 में तिलहन में एक प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ किया था।

दस से भी कम वर्षों में यानि 1986 से 1993 के बीच देश में दोगुना तिलहन उत्पादन हुआ जो उल्लेखनीय वृद्धि है, 1986–87 में तिलहन उत्पादन 11 लाख टन था जो 1993–94 में बढ़कर 22 करोड़ टन पर पहुंच गया। शुद्ध रूप से खाद्य तेल का आयात भारत इस मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया। खाद्य तेल में उसकी 97 प्रतिशत आत्मनिर्भरता थी और मात्र 3 फीसदी तेल आयात करने की आवश्यकता रह गई थी।

इसमें गिरावट तो कुछ साल बाद शुरू हुई जब भारत ने जानबूझ कर आयात शुल्क घटाकर सस्ते और भारी सब्सिडी वाले खाद्य तेल को बाजार में आने की अनुमति दे दी। जितना अधिक खाद्य तेल आयात किया गया, उतनी अधिक संख्या में घरेलू तेल प्रसंस्करण उद्योग बंद होते गए।

वर्ष 2002–03 में जब प्रो–एग्रो अपनी जीएम सरसों को बाजार में लाने की कोशिश कर रहा था तब आयात 12 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। 13 सालों बाद अब जब दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ पेंटल नई जीएम सरसों डीएमएच 11 की पैरवी कर रहे हैं तब खाद्य तेलों का वार्षिक आयात बिल 60 हजार करोड़ पर पहुंच गया है। लेकिन आयात में खर्च बढ़ने का कारण तिलहन के उत्पादन में गिरावट नहीं है। यह वृद्धि तो त्रुटिपूर्ण आयात निर्यात नीति के कारण हुई है। इस नीति ने आयात शुल्क को लगभग शून्य कर दिया है। होना यह चाहिएए कि आयात शुल्क को 70 प्रतिशत या उच्चतम किया जाए (डब्ल्यूटीओ भारत को खाद्य तेलों पर आयात शुल्क अधिकतम 300 प्रतिशत करने की अनुमति देता है)। ऐसा करने से किसानों को तिलहन के अधिक दाम और

आयात में खर्च बढ़ने का कारण तिलहन के उत्पादन में गिरावट नहीं है। यह वृद्धि तो त्रुटिपूर्ण आयात निर्यात नीति के कारण हुई है।

सुनिश्चित बाजार मिलेगा। फिर देखिए हमारे किसान कैसे तेल की कमी को पूरा करते हैं।

अभी दावा किया जा रहा है कि जीएम सरसों से उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी एकदम बेतूकी बात है। यह तो बस जीएम सरसों की पैरवी का तरीका है। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई ज्ञात जीन (या जीन समूह) ही नहीं है जो उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है। दूसरा, कोई भी जीएम किस्म उतनी ही अच्छी होती है जितनी संकर किस्म होती है, जिसमें विदेशी जीन डाला जाता है। यहां तक कि यदि कोई जीन संकरण की प्रक्रिया को सरल करता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह फसल उत्पादकता को बढ़ाता है।

डॉ दीपक पेंटल, दिल्ली विश्वविद्यालय

अभी दावा किया जा रहा है कि जीएम सरसों से उत्पादन में २० से २५ प्रतिशत की वृद्धि होगी एकदम बेतूकी बात है।

पिछले 13 वर्षों में मैंने उपलब्ध सरसों के तेल की गुणवत्ता से कोई शिकायत नहीं सुनी है। हमारे देश में पारंपरिक रूप से सरसों का इस्तेमाल भोजन के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियों को सरसों का साग के रूप में पकाया जाता है। इसलिए इस फसल को केवल खाद्य तेल के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए। मैं कभी–कभी सरसों के तेल का उपयोग कान और नाक के रोगों के उपचार और नियमित रूप से शरीर की मालिश के लिए करता हूं। इसके अलावा सरसों के तेल का उपयोग कई पारंपरिक चिकित्सा योगों में किया जाता है। यही कारण है कि 2010 में बीटी बैंगन पर रोक लगाते हुए व्यक्ता की गई पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की चिंता और जीएम फसलों पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट की तकनीकी समिति की सिफारिशों का पालन करना आवश्यक है।

सरसों के तेल में बड़े पैमाने पर सस्ती तेल की मिलावट उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी परेशानी है। आजकल देखा गया है कि खुले में बेचा जा रहे मिलावटी सरसों के तेल (जिसमें ज्यादातर सस्ता बिनौला तेल या ताड़ का तेल मिलाया जाता है) में लाल मिर्च के घोल का छिड़काव किया जाता है ताकि इसे सुस्वादु बनाया जा सके और पकाते समय बेहतर गंध प्रदान की जा सके। एसोसिएशन आफ बायोटेक्नोलॉजी लेड इंटरप्राइजेस यदि सही और शुद्ध सरसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से एक उपभोक्ता जागरूकता अभियान आरंभ करने की मांग करता है तो यह उसकी बड़ी जन सेवा होगी। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश द्वारा जीएम फसलों पर प्रतिबंध के समय पेश की गई 19 पेजों की रिपोर्ट को नजरअंदाज क्यों कर रही है? क्या जीएम उद्योग इतना शक्तिशाली है कि जीईएसी एक पूर्व मंत्री के नेतृत्व में आरंभ हुई एक वैज्ञानिक बहस को नजरअंदाज कर देना चाहती है और जीएम फसलों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर होने वाले बुरे असर से जुड़ी चिंताओं को भूला देना चाहती है? ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

बुंदेलखंड
खेत के साथ सूखा आंखों का भी पानी

बुन्देलखण्ड के जुड़वा गाँव खिसनी बुजुर्ग और खिसनी खुर्द इस बात का जीता–जागता उदाहरण है कि प्रशासनिक लापरवाही किस तरह मौसम की मार के असर को कई गुना बढ़ा सकती है। इतिहास की किताबों में जब हम पढ़ते कि अंग्रेजों ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र की पूरी आबादी को कहीं और स्थानान्तरित करने की सिफारिश की थी तो हमें उनकी समझ पर रश्क होता है। अगर कल्पना साथ नहीं दे तो एक बार बुन्देलखण्ड होकर आइए। पहले से ही भीषण जलसंकट का शिकार बुन्देलखण्ड इलाका साल–दर–साल नई त्रासदियों का शिकार होता जा रहा है।

सिरकार लगातार सूखे के बावजूद पुराने हैंडपंप को गहरा करने जैसे वही घिसे-पिटे उपाय अपना रही है। उसे इस समस्या की जड़ तलाशनी चाहिए लेकिन वह टहनियाँ काटछाँट कर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री करना चाहती है।
– पूजा सिंह

लगातार कम होती बारिश, प्राकृतिक जलस्रोतों का खात्मा और भूजल के विवेकहीन दोहन ने बुन्देलखण्ड को बंजर रेगिस्तान बनाने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। पलायन के दृश्य यहाँ एकदम आम हैं। लम्बे अरसे से यहाँ के गाँवों से पलायन का सिलसिला जारी है। गर्वीले किसान शहरों में जाकर मजबूरन मजदूर बन रहे हैं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के झाँसी जिले के बंगरा विकासखण्ड के गाँव खिसनी बुजुर्ग और खिसनी खुर्द यहाँ की विभीषिका के जीते–जागते उदाहरण हैं। एक–दूसरे से सटे इन गाँवों को एक ही गाँव माना जाता है। जनवरी का महीना चल रहा है, जाड़ा पूरे शबाब पर है। पानी की कमी दूर करने के लिये सरकार ने यांत्रिक तकनीक अपनाई और जगह–जगह हैण्डपम्प खुदवाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। लेकिन यहाँ के कुएँ और हैण्डपम्प पूरी तरह सूख चुके हैं।

गाँव में पीने का पानी नहीं है। सूखे की सूचना ने सरकारी अमले की हलचल बढ़ा दी है लेकिन शोध और परम्पराओं से कट चुकी सरकार एक बार फिर वही गलती दोहराने जा रही है। यानी गाँव के सूखे हैण्डपम्पों में दोबारा बोरिंग कराई जा रही है। यहाँ टैंकर की

मदद से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

किसान के लिये जहाँ कुओं, तालाब और हैण्डपम्प में पानी सूख रहा है, वहीं सरकारी अमले की आँखों के सूखते पानी ने उनकी मुश्किल और बढ़ा दी है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार लगातार सूखे के बावजूद पुराने हैण्डपम्प को गहरा करने जैसे वही घिसे–पिटे उपाय अपना रही है। उसे इस समस्या की जड़ तलाशनी चाहिए लेकिन वह टहनियाँ काटछाँट कर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री करना चाहती है। यहाँ की कुल आबादी 9,000 है। यह समझना मुश्किल है कि बिना पानी के यहाँ जीवन कैसे चल रहा है और आगे कैसे चलेगा? खिसनी बुजुर्ग के 27 में से 25 हैण्डपम्प पूरी तरह सूख चुके हैं जबकि खिसनी खुर्द के 50 में से 22 हैण्डपम्प किसी तरह काम चला रहे हैं।

इस क्षेत्र में कई किसानों ने सूखे के कारण फसल खराब होने तथा कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या तक कर ली है। झाँसी के निकट ही मेढकी नामक गाँव के एक किसान ने तो कुएँ का पानी सूख जाने के बाद अपनी जान दे दी। पानी की कमी का कोई इलाज नहीं है। या तो पानी उपलब्ध कराया जाये या फिर लोग यहाँ से कहीं और चले जाएँ। लोगों ने पानी की कमी के चलते नहाना–धोना तक बन्द कर दिया है क्योंकि बचे हुए पानी को वे खाने–पीने जैसे जरूरी कामों में इस्तेमाल करते हैं। खिसनी बुजुर्ग के निवासी सुमेर सिंह बताते हैं कि इस वैश्य–ठाकुर बहुल गाँव की सुध सरकार ने पहली बार 1977 में ली थी। पानी की समस्या को देखते हुए यहाँ हैण्डपम्प और कुओं की व्यवस्था की गई।

हालांकि यह तरीका बहुत कारगर नहीं हो सका क्योंकि यह पूरा इलाका पहाड़ी पर स्थित है। बाद में लोगों ने कुओं में पम्प लगाकर भी पानी निकालने की कोशिश की लेकिन बहुत लम्बे समय तक और अधिक सफलता नहीं मिल सकी।

मउरानीपुर में जंगलात विभाग के रेंजर देवेंद्र सिंह कहते हैं कि सरकार का पूरा ध्यान हैण्डपम्प पर ही केन्द्रित है। पुराने कुओं और बावडध्यिों के जीर्णोद्धार की बात तो तब पैदा होती है जब उनमें जरा भी पानी हो। लेकिन वर्षों से बनी अवर्षा की स्थिति ने पानी के किसी भी प्राकृतिक स्रोत में जरा सा भी पानी शेष नहीं रहने दिया है।

ऐसे में उनके जीर्णोद्धार या नए कुएँ, तालाब खोदने से कुछ मदद मिल पाएगी या नहीं इसमें वह सन्देह ही जताते हैं। आसपास के जंगलों में रहने वाले जंगली जानवर अपना काम घने जंगलों में बने एक तालाब से चला लेते हैं जो हरियाली तथा तमाम अन्य वजहों के चलते सूखने से बच गया है। लेकिन यहाँ के रहवासियों के पानी की समस्या जस–की–तस है।

सरकार जितने प्रयास यहाँ पानी उपलब्ध कराने को लेकर कर रही है उससे कई गुना अधिक उपाय उसे यह शोध करने में करना चाहिए कि आखिर बुन्देलखण्ड ऐतिहासिक तौर पर इस गहन जल संकट से क्यों गुजर रहा है।

एक अन्य स्थानीय व्यक्ति भवानी ठाकुर बताते हैं कि सूखे की वजह से यहाँ की तकरीबन 40 फीसदी आबादी दूसरे स्थानों पर पलायन कर चुकी है। स्थानीय लोगों ने अपने पशुओं को खुला छोड़ दिया है क्योंकि उनके पास अपने पीने के लिये पानी ही नहीं है तो वे भला पशुओं को कहाँ से पिलाएँगे। अगर पीने और अन्य जरूरी कामों तक के लिये पानी नहीं है तो खेती किसानी तो बहुत दूर की बात हो जाती है। गाँव में 15–20 ट्रैक्टर हैं लेकिन सबके सब दिखावा बने हुए हैं। खेती करने के लिये मूलभत चीज का अभाव है, पानी नदारद है। गाँव में तकरीबन 30–35 लोग नरेगा योजना के तहत रोजगारशुदा हैं।

गाँव की विभीषिका की खबर जब अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान आर एस यादव के नेतृत्त्व में एक टीम जमीनी हालात का जायजा लेने पहुँची। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की और कई बोरिंग को और अधिक गहरा करने का निर्देश जारी कर दिया गया।

स्थानीय जनपद पंचायत के सदस्य प्रीतम सिंह कहते हैं कि पानी की कमी की समस्या आज से नहीं है। बुन्देलखण्ड का पूरा इलाका अब इस समस्या के हल होने को लेकर पूरी तरह नाउम्मीद हो चला है। इस क्षेत्र में कई किसानों ने सूखे के कारण फसल खराब होने तथा कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या तक कर ली है। झाँसी के निकट ही मेढकी नामक गाँव के एक किसान ने तो कुएँ का पानी सूख जाने के बाद अपनी जान दे दी।

पानी की कमी का कोई इलाज नहीं है। या तो पानी उपलब्ध कराया जाये या फिर लोग यहाँ से कहीं और चले जाएँ। लोगों ने पानी की कमी के चलते नहाना–धोना तक बन्द कर दिया है क्योंकि बचे हुए पानी को वे खाने–पीने जैसे जरूरी कामों में इस्तेमाल करते हैं। पानी लाने के लिये लोगों को मीलों लम्बा सफर तय करना पड़ता है।

प्रीतम सिंह कहते हैं कि सरकार जितने प्रयास यहाँ पानी उपलब्ध कराने को लेकर कर रही है उससे कई गुना अधिक उपाय उसे यह शोध करने में करना चाहिए कि आखिर बुन्देलखण्ड ऐतिहासिक तौर पर इस गहन जल संकट से क्यों गुजर रहा है। विज्ञान और तकनीक के इस युग में यह असम्भव नहीं कि इस समस्या का निदान निकल आये। ❑❑

धूमिल होती संसद की गरिमा

सदन की कार्यवाही चलाने में कुल मिलाकर प्रति मिनट 29,000 रूपये का खर्च आता है। विगत शीतकालीन सत्र में 112 घंटे में से 55 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ गये। सोलहवीं लोकसभा की बात करें तो अभी तक संपन्न 6 सत्रों में सिर्फ पहला ही सत्र ऐसा रहा जिसमें सिर्फ 16 मिनट का समय बाधित हुआ।

– विद्यानंद आचार्य

भारत की संसदीय व्यवस्था विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सफल संसदीय व्यवस्था में शुमार है। संविधान निर्माताओं ने ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित की जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया ताकि राज्यतंत्र की व्यवस्था जिम्मेदारीपूर्वक एवं सुचारू रूप से चल सके। लेकिन पिछले कई वर्षों से भारतीय लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद को इसे चलाने वाले जन–प्रतिनिधियों ने अपने आचरण के द्वारा इसकी मर्यादा को तार–तार कर दिया है। जिस संसद में सांसदों के द्वारा देशहित, समाजहित में कानून बनाना चाहिए वहां आर्थिक, सामाजिक मुद्दों से जुड़े कानून पास होने की प्रतीक्षा में संसद के पटल पर, स्थायी समितियों के पास पड़े हुए हैं।

हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र पर यदि एक नजर डालें तो संसद ने निर्धारित समय का अधिकांश हिस्सा ऐसी चर्चाओं, बहसों में बिता दिया जिसे ''गैर विधायी चर्चा'' कह सकते हैं। कहने के लिए लोकसभा ने शीतकालीन सत्र में 98 प्रतिशत का समय चर्चा में व्यतीत किया लेकिन इस दरम्यान केवल 13 बिल पर 28 घंटा की बहस हो पायी। राज्यसभा की स्थिति तो और दयनीय रही। राज्यसभा में 9 बिल पर केवल 8 घंटे ही बहस हो पायी। ज्ञातव्य हो कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधि आते हैं वे अपने क्षेत्र की विशेषज्ञता प्राप्त किये रहते हैं। बावजूद इसके ''इमेज बिल्डिंग'' मुद्दे को प्राथमिकता देकर सांसद बहस में चेहरा चमकाते हैं और संसद की उत्पादकता को हाशिए पर डाल देते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के उत्पादकता में भी काफी अंतर है। शीतकालीन सत्र में लोकसभा ने 8 विधेयको को पास किया जबकि राज्यसभा ने 7 विधेयक पास किए, जिसमें 6 विधेयक ऐसे थे जो बिना चर्चा के ही पास कर दिए गए। 8 विधेयकों में प्रमुख विधेयक चीनी उत्पादन, बोनस वृद्धि, परमाणु ऊर्जा, बाल अपराध, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विषय से जुड़े थे। शीतकालीन सत्र की शुरूआत में 68 विधेयक संसद की पटल पर पास होने की प्रतीक्षा में पहले से लंबित थे जबकि चालू

सत्र में सरकार ने 10 विधेयक प्रस्तुत किया। पुराने और नए कुल मिलाकर 10 विधेयक पास हुए और सरकार ने 3 विधेयक वापस ले लिए। सत्र की समाप्ति पर 65 विधेयक लंबित ही रहे।

यह हाल तो हाल ही में संपन्न संसद के शीतकालीन सत्र का था। यदि सोलहवीं लोकसभा की चर्चा करें तो पंद्रहवीं लोकसभा की तुलना में थोड़ा भी अंतर दिखायी नहीं पड़ता है। यहां यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस ''अकार्यकारी'' संसद पर आम जनता का कितना पैसा पानी तरह बहाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार सदन की कार्यवाही चलाने में कुल मिलाकर प्रति मिनट 29,000 रूपये का खर्च आता है। विगत शीतकालीन सत्र में 112 घंटे में से 55 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ गये। यदि सोलहवीं लोकसभा की बात करें तो अभी तक संपन्न 6 सत्रों में सिर्फ पहला ही सत्र ऐसा रहा जिसमें सिर्फ 16 मिनट का समय बाधित हुआ। लेकिन पांचवे सत्र में 34 घंटे का कार्य बाधित हुआ। कुल मिलाकर 6 सत्रों में कुल 66 घंटे 4 मिनट का समय बर्बाद हुआ। प्रति मिनट खर्चे के हिसाब से यदि इन बर्बाद समय की गणना की जाए तो खर्चा करोड़ों रूपये मे आयेगा। कमोबेश यह हालत देश की सर्वोच्च संस्था के साथ–साथ राज्य की विधान सभाओं का भी है। इस बर्बादी में पक्ष–विपक्ष दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं। ज्ञातव्य हो कि ससंद का जबसे प्रत्यक्ष प्रसारण शुरू हुआ है तब से इस प्रकार की

देशहित और जनहित के मद्दे से जुड़े विधेयकों को बिना चर्चा–बहस के पास कर देना और 'पार्टी लाइन' से जुड़े मुद्दे पर निरर्थक चर्चा कर सदन की कार्यवाही को बाधित करना लोकतंत्र के भविष्य के हिसाब से काफी चिंताजनक है।

प्रवृत्तियां काफी बढ़ी हैं। जबकि देश का आवाम इस उम्मीद से सदन की कार्यवाही देखता है ताकि उनके प्रतिनिधि देशहित–जनहित के मुद्दों पर एकमत होकर सदन में उन नियमों एवं कानूनों पर विधान बनायेंगे। देशहित और जनहित के मद्दे से जुड़े विधेयकों को बिना चर्चा–बहस के पास कर देना और 'पार्टी लाइन' से जुड़े मुद्दे पर निरर्थक चर्चा कर सदन की कार्यवाही को बाधित करना लोकतंत्र के भविष्य के हिसाब से काफी चिंताजनक है।

एनडीए सरकार के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जब प्रथम दिन संसद में प्रवेश किया तो उन्होंने संसद के समाने माथा टेका था। शायद वह देश को यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि संसद देश के लोकतंत्र का मंदिर है। लेकिन सोलहवीं लोकसभा के अमूमन सभी सत्रों में विपक्ष एवं पक्ष के माननीय सदस्य द्वारा माहौल बनाया गया, वह कहीं से भी शोभनीय नहीं कहा जा सकता है। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों की राय है कि संसद चलनी चाहिए। लेकिन गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष की राय है कि वर्तमान सरकार जब विपक्ष में थी तब उन्होंने भी यही मार्ग अपनाया था। इसमें अहम भूमिका क्षेत्रीय दलों के सांसद निभा रहे हैं। दरअसल क्षेत्रीय दलों के सांसद चाहे वह किसी भी गढबंधन के साथ हो, कामकाजी बहस में हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं। उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि येन–केन–प्रकारेण पार्टी से जुड़े मुद्दे हो जोर–शोर से संसद में उठाना ताकि क्षेत्र की जनता और पार्टी के आका उन्हें फिर से पारितोषिक प्रदान कर सके। यहां यह कहना उचित होगा कि ससंद संसदीय कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने में जितनी भूमिका विपक्ष की है उससे अधिक भूमिका सत्ता पक्ष की भी है।

वर्तमान में द्विसदनात्मक संसद में लोकसभा में सत्तापक्ष को बहुमत प्राप्त है जबकि राज्यसभा में वह अल्पमत में है। वर्तमान विपक्ष के पास यह तुरूप का पत्ता साबित हो रहा है। कारण जो भी हो, लेकिन इससे कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन की पटल पर लंबित हैं और ये विधेयक पास होकर कब अधिनियम का रूप लेंगे, कहना मुश्किल है। उदाहरण के लिए 'वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)' विधेयक की बात लें तो इस एकमात्र विधेयक के लंबित रहने से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मार्च 2011 से यह विधेयक विभिन्न कारणों से संसद में लंबित रहा

सारणी–सोलहवीं लोकसभा में बाधित हुआ समय

सत्र	*बाधित हुआ समय*	*उठाये गए मुद्दे*
पहला सत्र	0.16 घंटे	34
दूसरा सत्र	13.51 घंटे	354
तीसरा सत्र	3.28 घंटे	271
चौथा सत्र	7.04 घंटे	412
पांचवा सत्र	34.04 घंटे	195
छठा सत्र	8.37 घंटे	358

है। हर बार सत्तापक्ष इस उम्मीद से इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करती है कि इस बार सदन इसे पास कर देगा लेकिन ऐसा 2011 से अभी तक संभव नहीं हो सका। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि 'जीएसटी' विधेयक पर सभी पक्षों में मौटे तौर पर आम सहमति बन चुकी है बावजूद इसके यह विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाया है।

अर्थशास्त्रियों की राय में जीएसटी विधेयक के लागू हो जाने की स्थिति में देश की वर्तमान 'जीडीपी' में 1–2 प्रतिशत तक की वृद्वि हो सकती है। तात्पर्य है कि 1–2 प्रतिशत की वृद्धि से 1–2 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था वर्तमान विकास दर में हर वर्ष जुड़ती जायेगी। अर्थात् 2011 से लंबित होने के कारण पिछले 5–6 वर्षों में लगभग 5–10 लाख करोड़ के योगदान से भारत की अर्थव्यवस्था वंचित रह गयी। देश में विकास की जितनी भी योजनाएं चल रही है, उनके आर्थिक सहयोग में इस अधिनियम की अहम भूमिका होती। क्या संसद को इन मुद्दों पर अलग से सत्र बुलाकर 'जीएसटी विधेयक' को पास नहीं कर देना चाहिए? तात्पर्य यह है कि संसद पर प्रति मिनट होने वाले खर्चों की तुलना में संसद में लंबित विधेयकों से देश को काफी घाटा हो रहा है।

संसद का वर्तमान स्वरूप जिस प्रकार उभरकर आया है वह हतोत्साहित करने वाला तो अवश्य है लेकिन 'सब समाप्त हो गया है', 'अब कुछ नहीं हो सकता है' यह समय भी नहीं आया है। संविधान की धारा 85 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला है कि वह किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर लंबित विधेयक को पास कराने के लिए सदन के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सके। ऐसा वह मंत्री परिषद के सुझाव पर कर सकता है। क्या अच्छा होता की संसद स्वयं बैठक यह तय करते कि संसद के सभी सत्रों की न्यूनतम संख्या कितनी हो और किसी भी स्थिति में उससे कम सत्र आहूतन न की जाए। संसद के पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक में इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होती है लेकिन दुर्भाग्यवश इसे स्वयं पर लागू करने से संसद परहेज करती है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि देश में उड़ीसा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वर्ष में विधानसभा की कितनी बैठकें करना अपरिहार्य है इसका विधान उन्होंने स्वयं कर लिया है।

समाज जीवन में निरंतर क्षरण होते मूल्यों का प्रभाव निश्चित रूप से समाज के सभी अवयवों पर पड़ता है। भष्ट्राचार, अपराधीकरण, भाई–भतीजावाद एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था में पैसा का बढ़ता प्रभाव आदि ने राजनेताओं एवं उनके साथ ही केंद्र और राज्य के विधान मंड़लों की छवि धूमिल की है। दरअसल लोकतंत्र का वर्तमान स्वरूप, जो यूरोपीय व्यवस्था की उपज है, का या तो यही हल होने वाला है या पुनः कायान्तरण के द्वारा एक नए स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर जन प्रतिनिधियों को यह समझना होगा कि विधान मंडल लोकतंत्र का मंदिर है और जनता ने उन्हें निर्वाचित कर उस मंदिर की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए भेजा ताकि वहां वार्ता, विवाद, संवाद, सहमति आदि के आधार पर जनहित और देशहित के मुद्दों से जुड़े कानून बनाकर राष्ट्र को निरंतर प्रगति की ओर ले जा सकें। ❑❑

श्रद्धांजलि

स्वर्गीय श्री सुंदर सिंह शक्रवार

स्वदेशी जागरण मंच के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विभाग प्रचार, सतना एवं भारतीय मजदूर संघ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष्य श्री सुंदर सिंह शक्रवार जी का लंबी अस्वस्थता के बाद दिनांक 1–2–2016 को देहावसान हो गया। स्वदेशी जागरण मंच के मध्य क्षेत्र के संयोजक के नाते लंबे समय तक कार्य करते हुए श्री सुन्दर सिंह शक्रवार जी ने संगठन को विस्तार तो दिया ही, उनके कार्यकाल के दौरान स्वदेशी जागरण मंच ने मध्य क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को छुआ। स्वर्गीय श्री सुन्दर सिंह शक्रवार जी छिन्दवाड़ा के जाने–माने अधिवक्ता थे। अपने व्यवसाय की व्यस्ताओं के बावजूद वे श्रमिक हितों के लिए निरंतर काम करते रहे। लंबे समय तक मध्य प्रदेश प्रशासन के श्रम कल्याण बोर्ड़ के भी वे अध्यक्ष रहे। श्रम कल्याण बोर्ड़ के अध्यक्ष के नाते भी उन्होंने श्रमिकों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया। उनके निधन से स्वदेशी आंदोलन को एक अपरिपूर्णीय क्षति पहुंची है। ❑

स्टार्ट-अपः नए उद्यमों का रोडमैप

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए उद्यमियों को मदद करने का संकल्प लिया है जिसका पुरजोर स्वागत करना चाहिए। देश के युवाओं के पास नए उद्योग लगाने के आइडिया हैं परंतु कार्यांवित करने के लिए पूँजी नही है। सरकार द्वारा इन्हें समर्थन देने से इनकी छिपी हुई उर्जा बाहर आ सकती है और देश को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन केवल आर्थिक मदद देने से काम नही बनेगा। सही वातावरण बनाना होगा। तमाम ऐसे आइडिया हैं जिन्हें कार्यान्वयित करने को पूँजी की जरूरत नही है। जैसे किसी सरकारी कर्मचारी ने फाइलों को ट्रेक करने का फार्म बनाया। इसे लागू करने को पैसा नही चाहिए। इस प्रकार के तमाम इन्नोवेशन है जिन्हें लागू किया जा सकता है। जरूरत है कि देश के नागरिकों में नए आइडिया के प्रति सकारात्मक रुख बनाया जाए।

इन्नोवेशन में सबसे बड़ी बाधा सरकारी यूनिवर्सिटी तथा लैबोरेटरी की निष्फलता है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के नए आइडिया को ग्रहण करने मे रुचि नही है। छात्रों के दिमाग को विकसित करने के स्थान पर वे उन्हें रटाकर परीक्षा पास कराना चाहते है। 95 प्रतिशत प्रोफेसर स्वयं इन्नोवेशन नहीं करते है तो वे छात्रों को इन्नोवेशन कैसे सिखाऐंगे? जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछता है उसे प्रोफेसर पद्धलित करते है। प्रश्न पूछने से छात्रों की सोचने की मनोवृति बनती है। इन्नोवेशन के लिए छात्रों को नए तरह से सोचने की छूट होनी चाहिए। जरूरी है कि प्रोफेसरों में इन्नोवेशन के प्रति सम्मान बनाया जाए। सरकार को चाहिए कि प्रोफेसरों को आजीवन रोजगार देने के स्थान पर पाँच वर्ष के ठेकों पर नियुक्त किया जाए। हर वर्ष छात्रों द्वारा उनका मूल्यांकन कराया जाए। चार वर्ष बाद बाहरी संस्था द्वारा उनके द्वारा किए गए इन्नोवेशन का आकलन किया जाए। इन्नोवेशन करने वाले प्रोफेसरों मात्र ठेकों का बढ़ाया जाए। ऐसा करने से हमारी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में इन्नोवेशन का प्रवेश होगा। बिना खर्च बढ़ाए इन्नोवेशन होने लगेगा। यही फार्मूला तमाम सरकारी लैबोरेटरी पर लागू करना चाहिए।

इन्नोवेशन को गति देने के लिए पेटेंट कानून पर सरकार को पुनर्विचार करना होगा। पेटेंट कानून में व्यवस्था है कि किसी तकनीक की नकल नही की जा सकती है।

– **डॉ. भरत झुनझुनवाला**

सरकार को छोटे उद्योगों को संरक्षण देना होगा। तब ही चौतरफा इन्नोवेशन होगा।

इन्नोवेशन को गति देने के लिए पेटेंट कानून पर सरकार को पुनर्विचार करना होगा। पेटेंट कानून में व्यवस्था है कि किसी तकनीक की नकल नही की जा सकती है। जैसे किसी कंपनी ने बीटी काटन के बीज का पेटेंट करा लिया। इसके बाद इस बीज को बनाने अथवा इसमें सुधार करने का दूसरों का अधिकार समाप्त हो जाता है। इन्नोवेशन रूक जाता है। मान लीजिए किसी किसान ने बीटी काटन का बीज बनाने का सस्ता तरीका ढूढ़ लिया। पेटेंट कानून के अंतर्गत किसान को अधिकार नही है कि इस सस्ते बीज को बनाकर बेच सके चूँकि बीज पर किसी कंपनी का पेटेंट है। इस प्रकार पेटेंट कानून से इन्नोवेशन बाधित होता है। दूसरी तरफ पेटेंट कानून से बड़ी कंपनियों द्वारा इन्नोवेशन को बढ़ावा मिलता है।

पेटेंटीकृत माल को मंहगा बेचकर ये कंपनियाँ भारी लाभ कमाती है। कमाई गई रकम का निवेश में नई तकनीको के इन्नोवेशन में लगाती है। जैसे माइक्रोसाफ्ट ने विन्डोज़ साफ्टवेयर बनाकर लाभ कमाया फिर कमाई से नया सर्च इंजन बनाया। इस प्रकार पेटेंट कानून से इन्नोवेशन बाधित भी होता है और प्रोत्साहित भी होता है। अंतर यह है कि पेटेंट कानून में ढील देने से जनसामान्य के द्वारा इन्नोवेशन को बढ़ावा मिलता है जबकि पेटेंट कानून के सख्त होने पर बड़ी कंपनियों द्वारा इन्नोवेशन को बढ़ावा मिलता है। अतः यदि प्रधानमंत्री देश के युवाओ द्वारा इन्नोवेशन को बढ़ावा देना चाहते है तो उन्हें पेटेंट कानून में ढील देनी चाहिए।

इन्नोवेशन को बढ़ावा देने का तीसरा क्षेत्र छोटे उद्योग है। देश में यदि 10 बड़े उद्योग हैं तो 1000 छोटे उद्योग है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने से 1000 लोग इन्नोवेशन करेंगे। नए तरीकों से माल बनाऐंगे इत्यादि। इन्नोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रोत्साहन देना होगा। लेकिन छोटे उद्योगो द्वारा माल बनाने में लागत ज्यादा आती है। आज भारतीय उ़द्योग चीनी उद्योगो द्वारा पीटे जा रहे है चूँकि ये तुलना में छोटे है और इनकी लागत ज्यादा आ रही है। इसी प्रकार देश के छोटे उद्योग देश के बड़े उ़द्योगों द्वारा पीटे जा रहे है चूँकि इनकी लागत ज्यादा आती है।

छोटे उद्योगों द्वारा इन्नोवेशन कम किया जा रहा है चूँकि ये दबाव में है। हजारों छोटे उद्योगों द्वारा इन्नोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्हें बड़े उद्योगों से संरक्षण देना होगा उसी तरह जैसे चीन में बने सस्ते माल पर एन्टी–डम्पिंग ड्यूटी लगाकर भारतीय उद्योगों को संरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन भारत सरकार बड़ी कंपनियों को आकर्षित करना चाहती है जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के द्वारा। फलस्वरूप छोटे उद्योग दबाव में है और बड़े उद्योग फलफूल रहे हैं। हजारों छोटे उद्योगों द्वारा इन्नोवेशन नहीं किया जा रहा है और मुट्ठी भर बड़े उद्योगों तक इन्नोवेशन तक सिमट गया है। पूरे देश को इन्नोवेशन में लगाने के लिए सरकार को छोटे उद्योगों को संरक्षण देना होगा। जिस प्रकार सरकार परिवार द्वारा बच्चे को 21 वर्षों तक कालेज में पढ़ाने का खर्च उठाया जाता है उसी प्रकार देश को छोटे उद्योगों द्वारा इन्नोवेशन करने को खर्च उठाना पड़ेगा। तब ही चौतरफा इन्नोवेशन होगा।

छोटे उद्योगों को संरक्षण देने से उद्यमिता का विकास भी होगा और रोजगार भी उत्पन्न होंगे। अतः सरकार को निर्णय करना होगा कि वह छोटे उद्योगों द्वारा मंहगा माल बनवाकर हजारों से इन्नोवेशन कराना चाहती है अथवा बड़े उद्योगों द्वारा सस्ता माल बनवाकर मुट्ठी भर उद्योगों द्वारा इन्नोवेशन कराना चाहती है। छोटे उद्योगों द्वारा मंहगा माल बनाने से इन्नोवेशन ज्यादा होगा और आने वाले समय में माल सस्ता बनेगा। तुलना में आज बड़े उद्योगों द्वारा सस्ता माल बनाने से इन्नोवेशन कम होगा और आने वाले समय में माल मंहगा बनेगा। अतः विषय देश के अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन दिन के बीच चयन करने का है। छोटे उद्योगों को संरक्षण देने से दीर्घकालीन हित हासिल होगा जबकि बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने से अल्पकालीन हित हासिल होगा।

प्रधानमंत्री ने इन्नोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट–अप यानी नए उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का मन बनाया है। यह सही दिशा में कदम है। लेकिन सरकार की वित्तीय हालत खस्ता है। इसलिए उन कदमों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिनके द्वारा बिना खर्च के इन्नोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए युनिवर्सिटी में ठेकों पर नियुक्ति, पेटेंट कानून में ढील देना तथा छोटे उद्योगों को संरक्षण देना जरूरी है। ❑❑

आधुनिक शिक्षा बनाम गुरूकुल पद्धति

भारत में ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत बड़े–बड़े महापुरूष हुए हैं, जैसे शुश्रुत, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, नीलकण्ड, पतंजलि, चाणक्य और कन्नाद आदि अनेक नाम हैं, अगर सभी के नाम लिखे जाएं तो यह लेख नामों से ही भर जाएगा, परंतु अंग्रेजों से पहले की भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में अधिकतर भारतीय जानते ही नहीं और कुछ तो यह समझते हैं कि अंग्रेजों से पहले भारत में शिक्षा थी ही नहीं। भारत को 1947 में मिली तथाकथित आजादी से पहले देश की जिन महान विभूतियों को प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के संबंध में जानकारी थी और उन्हें विश्वास था कि आजादी मिलने के बाद भारत में वही शिक्षा व्यवस्था लौट आएगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। आजादी के बाद भी भारत में वही मैकॉले शिक्षा व्यवस्था लागू रही और समय के साथ–साथ पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की शिक्षा व्यवस्था एवं महापुरूषों का ज्ञान कम होता गया। आज वह विलुप्त होने की कगार पर है।

भारत में धारणा है कि जिस क्षेत्र में एक श्रेष्ठ व्यक्ति रहता है उसका प्रभाव युगों–युगों तक उस क्षेत्र में रहता है। प्राचीन काल में अहमदाबाद में महर्षि दधीचि का आश्रम रहा है, जिन्होंने न्यायसंगत युद्ध के लिए अपनी हड्डियों तक का दान दे दिया था। वहीं भारत की गुलामी के समय देशभक्तों ने अपने जीवन को दाव पर लगाते हुए आजादी की लड़ाई के लिए अहमदाबाद को केंद्र बनाया। आज इसी धारणा को प्रबल करते हुए उसी अहमदाबाद को 'हेमचंद्राचार्य संस्कृत–पाठशाला' नामक गुरूकुल के संचालक उत्तमभाई (7927501944, 9033543543, 98980990066) ने भारत को प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से विश्व गुरू बनाने के संकल्प के साथ अपना केंद्र बनाया है।

आजादी के बाद भी भारत में वही मैकॉले शिक्षा व्यवस्था लागू रही और समय के साथ-साथ पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की शिक्षा व्यवस्था एवं महापुरूषों का ज्ञान कम होता गया। आज वह विलुप्त होने की कगार पर है।
– मनोज भारत

आज भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का अनुसरण करने के लिए पूरा भारतीय समाज जहां दौड़ रहा है वहीं भारत में हेमचंद्राचार्य संस्कृत–पाठशाला में स्वदेशी शिक्षा पद्धति अर्थात् गुरूकुल व्यवस्था के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस गुरूकुल की व्यवस्था पूरे

भारत में चल रहे शिक्षण संस्थानों से अलग है। इस गुरूकुल में कोई डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। मैंने प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था की विशालता और श्रेष्ठता के बारे में कई महान लेखकों की पुस्तकों में पढ़ा था, लेकिन उस व्यवस्था को अपनी आंखों से देखने का मौका मुझे इसी गुरूकुल में मिला।

अहमदाबाद के गणपति विश्वविद्यालय में गुजरात के 1500 विद्यालयों के लगभग 3000 श्रेष्ठ विद्यार्थियों और इतने ही अध्यापकों के समारोह में मुझे शिरक्त करने का मौका मिला। इस समारोह में हेमचंद्राचार्य संस्कृत–पाठशाला के विद्यार्थियों को अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में गुरूकुल के विद्यार्थियों ने संगीत, नाटक, मलखम्ब आदि कई क्षेत्रों में अपने जौहर दिखाए। इसके साथ ही आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ना और संस्कृत में वार्तालाप जैसे कलाएं भी हमें वहां देखने को मिली। इस कार्यक्रम का जो आनंद मैंने महसूस किया और दर्शकों ने भी तालियों से जो आनंद दर्शाया वह शब्दों में ब्यान नहीं किया जा सकता।

इस पाठशाला को चलाने वाले उत्तम भाई ने बताया कि इस शाखा में 80 विद्यार्थी हैं और जिन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए 130 गुरू आते हैं। भारत में जब गुरूकुल व्यवस्था से शिक्षा प्रदान की जाती थी तब भारत विश्व गुरू कहलाता था और भारत में विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी आया करते थे। लेकिन 1835 में जबसे भारत में मैकॉले शिक्षा पद्धति से शिक्षा दी जाने लगी तभी से शिक्षा का स्तर गिरना शुरू हो गया जो आज पूरे समाज में बढ़ रही बैरोजगारी, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, महिलाओं के साथ होते अत्याचार आदि गंभीर समस्याओं के रूप में हमें नजर आ रहा है। उत्तमभाई किसी भी

अक्षर ज्ञान न तो शिक्षा का आरंभ है और न अंतिम लक्ष्य। वह तो उन अनेक उपायों में से एक है, जिनके द्वारा स्त्री–पुरूषों को शिक्षित किया जा सकता है।

आधुनिक बौद्धिक को गुरूकुल के छात्र के साथ किसी भी विषय पर बहस में मुकाबला स्वीकार करने की चुनौती देते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक विद्यालयों में शिक्षा नहीं दी जाती केवल अक्षर ज्ञान दिया जाता है और शिक्षा के संबंध में गांधी जी ने भी कहा था कि अक्षर ज्ञान न तो शिक्षा का आरंभ है और न अंतिम लक्ष्य। वह तो उन अनेक उपायों में से एक है, जिनके द्वारा स्त्री–पुरूषों को शिक्षित किया जा सकता है। फिर सिर्फ अक्षर ज्ञान को शिक्षा कहना गलत है।

भारतीय संस्कृति पर आधारित इस गुरूकुल में सुबह साढे चार बजे विद्यार्थियों की दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है और रात साढ़े नौ बजे तक जारी रहती है। अपनी दिनचर्या में विद्यार्थी शिक्षण के साथ–साथ अपने पारंपरिक खेलों, नैतिक शिक्षा, न्याय, संस्कृत, आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और संगीत आदि का ज्ञान और आनंद प्राप्त करते हैं। इस गुरूकुल में भारत के साथ–साथ विदेशों के समृद्ध परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गुरूकुल के एक छात्र के पिता श्री निदेश शाह जोकि दुबई में रहते हैं, का कहना था कि आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों से बच्चे जब निकलते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं जैसे जेल से छूटे हों और जब माता–पिता उन्हें भेजते हैं तो ऐसे तैयार करते हैं जैसे युद्ध लड़ने जा रहे हों, लेकिन इस विद्यालय में बच्चों को घर जैसे माहौल में शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में ज्यादा आसानी होती है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान इस गुरूकुल की सराहना भी की थी। उनके अतिरिक्त योग गुरू बाबा रामदेव, पंचखण्ड पीठाधीश्वर आचार्य श्री धर्मेन्द्र जी महाराज, वरिष्ठ पत्रकार वेदप्रताप वैदिक, वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण, समाज सेवी अन्ना हजारे और विश्व हिन्दू परिषद के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया आदि देश के अनेक प्रबुद्ध लोगों ने भी गुरूकुल का भ्रमण किया और साथ ही उत्तमभाई के इन प्रयासों की सराहना की।

इस गुरूकुल के तुषार नामक एक विद्यार्थी ने अभी हाल ही में वैदिक गणित की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करते हुए गोल्ड मैडल प्राप्त किया है। इस गुरूकुल के विद्यार्थी संस्कृत, हिन्दी, गुजराती व अंग्रेजी में बोलने और बात करने में बिल्कुल सहज महसूस कर रहे थे। हर व्यक्ति के मन में श्रेष्ठ शिक्षा का नाम आते ही दिमाग में उस शिक्षा के लिए होने वाले खर्च का विचार आता है। उत्तमभाई ने इस संबंध में जो कहा वह सुनकर हम हैरान रह गए। उनका कहना था कि भारत में कभी शिक्षा बेची नहीं जाती थी वह तो सुपात्र को दी जाती थी और इसी आधार पर यह गुरूकुल चलता है। मुझे और मेरे साथियों को यह देखकर ओर भी आश्चर्य हुआ कि केवल शिक्षा ही नहीं इस गुरूकुल में रहने वाले विद्यार्थियों को जैविक अनाज और गुरूकुल की ही गायों से प्राप्त दूध व घी आदि भी निःशुल्क दिया जाता है। हमने भी विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का आनंद लिया। इतना गहरा अनुभव मैंने प्राप्त किया कि उसे इस लेख में पूरा कर पाना मुश्किल है यह तो केवल उस गुरूकुल के भ्रमण से ही प्राप्त हो सकता है। ❑❑

भारत में किसान आत्महत्याओं का सच

आत्महत्या एक अंतिम कदम है, मनुष्य उसे तब उठाता है, जब अपने आपको अकेला, असहाय महसूस करता है। जो अपनो का भी प्यार खो चूका होता है और जिसे सर्वदूर केवल प्रतारना ही सहन करनी पडती है। जो सहायता के लिये मनोमन प्रार्थना करता है, लेकिन उसे बदले में उपेक्षा, तिरस्कार ही मिलता है। उसके लिये जीने के सारे रास्ते बंद हो जाते है, तब वह अंतिम कदम उठाने के लिये मजबूर होता है। यह परिस्थिति कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। लेकिन उसके मूल में मुख्यतः गरीबी और उससे उपजा तनाव है। आत्महत्या का सच इसी वास्तविकता को उजागर करता है।

भारत में आत्महत्याएं एक गंभीर और चिंता का विषय बन गया है। नेशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो 2014 (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2014 में 1 लाख 31 हजार 666 आत्महत्याएं हुई हैं। गत दस साल में एक लाख लोगों में 11 की दर से प्रति वर्ष आत्महत्याएं हो रही है। भारत में प्रतिदिन 361 आत्महत्याएं और एक घंटे में 15 आत्महत्याएं हो रही है।

रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्याओं के प्रमुख कारणों में पारिवारिक समस्याएं, बीमारी, दिवालियापन या ऋणग्रस्तता, परीक्षा में विफलता, विवाह से संबंधित मुद्दे, नशीली दवाओं के सेवनध्लत, प्रेम प्रकरण, सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट, दरिद्रता, बेरोजगारी, संपत्ति विवाद, अज्ञात कारण और अन्य कारण का समावेश है।

एन.सी.आर.बी. 2014 की रिपोर्ट में आत्महत्या ग्रस्त पीडितों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर विभाजित किया गया है। आर्थिक स्थिति के बारे में दी जानकारी के अनुसार कुल आत्महत्याओं में 91,820 (69.7 प्रतिशत) पीडित परिवार की आय 1 लाख से कम रही है और 35,405 (26.7 प्रतिशत) पीडित परिवार की आय 1 से 5 लाख के बिच रही है। 785 (0.6 प्रतिशत) पीडित परिवार 10 लाख से ज्यादा आय प्राप्त करने वाले है।

कुल आत्महत्याएं	वार्षिक आय			
	1 लाख से कम	*1–5 लाख*	*5–10 लाख*	*10 लाख से अधिक*
131666	91820	35405	3656	785
100 %	69.7 %	26.9 %	2.8 %	0.6 %

उसके लिये जीने के सारे रास्ते बंद हो जाते है, तब वह अंतिम कदम उठाने के लिये मजबूर होता है। यह परिस्थिति कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। लेकिन उसके मूल में मुख्यतः गरीबी और उससे उपजा तनाव है।
– विवेकानंद माथने

कुल आत्महत्याएं	शैक्षिक स्थिति				
	8 वी से कम	*8वीं–10वीं*	*10वीं–12वीं*	*उच्च शिक्षा*	*अज्ञात स्थिती*
131666	70364	27002	14428	5629	14243
100%	53.5%	20.5%	11%	4.2%	10.8%

शैक्षिक स्थिति के अनुसार 85 प्रतिशत पीड़ित 12वीं से कम पढ़े थे, उसमें 74 प्रतिशत 10वीं से कम पढ़े है, 8वीं से कम पढ़े पीडितों की संख्या 53. 5 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत पीडित उच्च शिक्षित हैं।

पेशा आधारित आत्महत्या में देश की कुल आत्महत्याओं में 8.1 प्रतिशत आत्महत्याएं पेशावर/वेतनभोगी/पेंशनर लोगों की है। बाकी सभी आत्महत्याएं किसान, खेती मजदूर, गृहिणी, विद्यार्थी, बेरोजगार, स्वयं रोजगार, दैनिक मजदूर व अन्य की है।

भारत के शहरों और गावों में हो रही आत्महत्याएं गरीबी, अशिक्षा और असुरक्षित रोजगार से गहरा रिश्ता दर्शाती है। यह स्पष्ट करता है कि अधिकांश आत्महत्याएं गरीबी से उपजे कारणों से हो रही है। यह वास्तव व्यवस्था का क्रूर, हिंसक और विक्राल रुप उजागर करता है, देश की विकास नीति का फर्दाफाश करता है। यह भेदभाव पूर्ण, अन्यायकारी नीतियों का परिणाम है। आर्थिक विषमता पर आधारित समाज व्यवस्था का परिणाम है।

एन.सी.आर.बी. 2014 की रिपोर्ट में गांव और नगरों में हुई आत्महत्याओं को स्वतंत्र रुप से नही दर्शाया गया है। साथ ही किसान परिवार में हुई आत्महत्या को भी अलग से उल्लेखित नहीं किया है, लेकिन यह अनुमान किया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 68.8 प्रतिशत जनता ग्रामीण भारत में बसती है और इसमें अधिकांश लोग खेती या खेती पुरक रोजगार पर निर्भर है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1,31,666 गुना 68.8 प्रतिशत ग्रामीण भारत की जनता बराबर 90586 आत्महत्याएं ग्रामीण भारत में हो रही है और 41,080 आत्महत्याएं नगरों में हो रही है। ग्रामीण भारत में प्रतिवर्ष 90,586 आत्महत्याएं हो रही है। प्रतिदिन 248 आत्महत्याएं और प्रति घंटा 10 आत्महत्याएं हो रही है।

एक व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह भी चिंता का विषय है। लेकिन हर साल लगातार हजारों किसानों की आत्महत्याएं सरकार के लिये चिंता का विषय नहीं है। सरकारें किसानों की आत्महत्याओं का सच छुपाने का जानबुझकर प्रयत्न करती है। उसके लिये वह नये–नये तरीके ढूंढ़ती है। एन.सी.आर.बी. की रीपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2014 में 12360 किसानों ने आत्महत्या की है। किसान की सदोष व्याख्या करके आत्महत्याएं कम दिखाने का प्रयास किया जाता है। कई राज्यों में किसान आत्महत्या को अन्य में वर्गीकृत किया जाता है।

सरकारें किसानों की आत्महत्याओं का सच छुपाने का जानबुझकर प्रयत्न करती है। उसके लिये वह नये–नये तरीके ढूंढ़ती है।

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सितंबर 2014 में एक केस में (याचिका क्र.–W.P.(C) No.134 of 2013) दिये जवाब में कहती है कि देश में हो रही कुल आत्महत्याओं में किसान आत्महत्या का प्रतिशत केवल 8.73 प्रतिशत है। किसानों की आबादी की तुलना में यह आत्महत्याओं की संख्या बहुत कम है। इसलिये चिंता का विषय नही है। लोकसभा में 8 जुलाई 2014 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न क्र. 81 के जवाब में भारत के कृषिमंत्री ने किसानों के आत्महत्या के कारणों में प्रेम प्रकरण और नपुसंकता को किसानों की आत्महत्या का एक कारण बताने में शर्म महसूस नही की। यह नीति निर्धारकों का संवेदना शून्य और किसान विरोधी होने का स्पष्ट प्रमाण है।

भारत सरकार द्वारा हर साल एन. सी.आर.बी. की रिपोर्ट पेश की जाती है। उसमें पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर देश में की गयी आत्महत्याओं की संख्या दी जाती है। लेकिन भारत की पुलिस और महसूल विभाग का कर्मचारी आत्महत्या के कारणों के सही सामाजिक विश्लेषण के आधार पर आत्महत्याओं को वर्गीकृत करने में सक्षम नही है। आमतौर पर जिसके नाम पर खेती और कर्ज है, ऐसे आत्महत्या को ही किसान की आत्महत्या माना जाता है।

यहां यह समझना होगा कि किसान की आर्थिक स्थिति पूरे परिवार को प्रभावित करती है। खेती पूरे किसान परिवार के जीवन का आधार है। इसलिये किसान के साथ–साथ किसान परिवार में हो रही आत्महत्या की भी गिनती की जानी चाहिये। हजारों किसान परिवारों में हुई आत्महत्याएं खेती किसानी के संकट से उपजे कारणों से हो रही है। आत्महत्याओं के विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि देश में किसान परिवार में हो रही आत्महत्याएं किसानों की घोषित आत्महत्याओं से कई गुना आधिक है, जिससे किसान आत्महत्याओं का अति भयंकर वास्तव सामने आता है।

कृषि परिवार की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण 2013 के अनुसार ग्रामीण भारत

के कुल 15.61 करोड परिवारों में 9.02 करोड (57.8 प्रतिशत) किसान परिवार है। कुल किसान परिवारों में 8.65 करोड (95.90 प्रतिशत) किसान परिवार एक लाख रुपये से कम आय प्राप्त करते है। 52 प्रतिशत किसान परिवार ऋणग्रस्त है। प्रति किसान परिवार औसत 47000 रुपये का ऋण अनुमान किया गया है। 36 प्रतिशत किसान परिवारों के पास बी.पी.एल. कार्ड और 5 प्रतिशत किसान परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड है। सर्वेक्षण की अवधि के दौरान देश में लगभग 44 प्रतिशत कृषि परिवारों के पास मनरेगा जॉब कार्ड था। यह सर्वेक्षण यह स्पष्ट करता है कि देश का अन्नदाता किसान गरीबी का जीवन जी रहा है।

गावों में रहने वाले किसान परिवार की संख्या एक लाख से कम आय प्राप्त करने वाले किसान परिवार की संख्या और वास्तविकता के आधार पर यह अनुमानित किया जा सकता है कि कुल ग्रामीण आत्महत्याओं में 70 प्रतिशत से अधिक आत्महत्या किसान परिवार में हो रही है। इसके आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि कुल ग्रामीण आत्महत्याएं 90586 गुना 70 प्रतिशत किसान परिवार में आत्महत्या बराबर 63410 आत्महत्याएं किसान परिवार में हो रही है। अर्थात ग्रामीण भारत के किसान परिवार में प्रतिवर्ष 63410 आत्महत्याएं हो रही है। ग्रामीण भारत के किसान परिवार में प्रतिदिन 174 और एक घटें में 7 आत्महत्या हो रही है।

देश में एक घंटे में हुई कुल 15 आत्महत्याओं में से 10 आत्महत्याएं ग्रामीण भारत में हो रही है, जिसमें 7 आत्महत्याएं किसान परिवार में हो रही है। किसानों की यह आत्महत्याएं किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं बल्कि अब पूरे देश में हो रही है। यह वास्तव भारत में किसानों की दुर्दशा को प्रदर्शित करती है।

शहरों में गरीबी का जीवन जीने वाले अधिकांश लोग गांव से ही आये है। जो गांव में किसानी या खेती मजदूरी या खेती आधारित रोजगार या स्वयंरोजगार करते थे। शहरों में बसी गांव की आबादी, गांव की बदहाली की स्थिति, कृषि पर हमला और गांव के रोजगार छिने जाने का परिणाम है। आत्महत्याग्रस्त लोगों में गांव के खेती आधारित रोजगार करने वाले पीडितों की और गांव से शहरों में विस्थापित पीडितों की संख्या जोडी गयी तो किसान परिवार में हो रही आत्महत्याओं की संख्या और अधिक बढ़ेगी।

किसान आत्महत्या का सच छुपाने के बजाए देश के सामने रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिये आवश्यक है कि किसान परिवार में हो रही आत्महत्याओं को रेकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिये।

विवेकानंद माथने, आजादी बचाओ आन्दोलन, किसान स्वराज आन्दोलन, मो.: 09822994821,
ई–मेलः vivekanand.amt@gmail.com

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

राज्यों को मेक इन इंडिया के लिए भारी अनुदान

भारत सरकार ने भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने तथा प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' अभियान पर जोर देने के लिए पांच परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारी उद्योग विभाग की "भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धी क्षमता" शीर्षक वाली योजना के जरिए लगभग 175 करोड़ रुपए के अनुदान के रूप में सरकारी सहायता मुहैया कराई जाएगी। नवंबर 2014 में शुरू हुई इस योजना में 975 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावध ाान है, जिसमें 580 करोड़ रुपए का अनुदान अंश भी शामिल है।

पहली परियोजना भारत सरकार तथा कर्नाटक सरकार के बीच एक संयुक्त उपक्रम से संबंधित है। इसके अंतर्गत एनएमआईजेड, टुमकुर में जापानी पार्क के नजदीक अपनी तरह के पहले एकीकृत मशीन कलपुर्जा पार्क के निर्माण के लिए 500 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है। 421 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना भारत सरकार की 125 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता द्वारा आंशिक रूप से पूरी की जाएगी।

दूसरी परियोजना पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर में वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने से संबंधित है। पीएसजी ने वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान, वेल्डिंग उपकरण/उत्पाद निर्माता तथा फिक्की आदि जैसे प्रमुख साझेदारों के सहयोग से एक आधुनिक वेल्डिंग प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारतीय निर्माताओं को केन्द्र द्वारा विकसित नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाकर सहायता प्रदान करेगा। यह प्रौद्योगिकी वेल्डिंग मशीन के स्वदेश निर्मित कलपुर्जे, उपभोग्य सामग्री तथा स्थानीय रूप से प्रशिक्षित श्रमशक्ति से संबंधित है जिनमें विशेष रूप से ऐसे वेल्डिंग कार्य हैं जिनमें माहिर लोगों की जरूरत होती है तथा सामरिक क्षेत्रों को इनकी आवश्यकता होती है। संपूर्ण बजट (पीएसजी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा) जिसमें भूमि तथा भवन शामिल नहीं है, की अनुमानित राशि 26.7 करोड़ रुपए है। इनमें से सरकार 21.10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी तथा शेष राशि उद्योग तथा संस्थान उपलब्ध कराएंगे।

तीसरी स्वीकृति एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड को दी गई है, जो कि एक पीएसयू है जिसने भारत में मशीन कलपुर्जे उद्योग की स्थापना करने तथा उसके विकास में पथ प्रदर्शक का काम किया है। नवीनतम खराद तथा चक्की केन्द्र का निर्माण करके इस प्रस्ताव द्वारा एचएमटी अपने उत्पाद संविभाग का आधुनिकीकरण कर रही है। इसके लिए विश्व के अग्रणी औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संस्थान, जर्मनी के मेसर्स फ्रोनहोफर के साथ वह सहयोग कर रही है। इसके परिणामस्वरूप एचएमटी रेलवे, रक्षा, जहाजरानी, उड्डयन तथा एयरोस्पेस आदि को अत्याधुनिक तथा नवीनतम मशीनों की आपूर्ति कर सकेगी। कंपनी को 1.54 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण की दिशा में कंपनी द्वारा लिए जाने वाला यह पहला कदम होगा।

चौथा प्रस्ताव एचईसी, रांची से है, जो भारी इंजीनियरिंग उपकरण निर्माण के क्षेत्र में एक केन्द्रीय पीएसयू है। यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित एचईसी भारी इंजीनियरिंग उपकरण निर्माण में शीर्ष में है जिसके साथ विश्व में कम ही कंपनियां मुकाबला कर सकती हैं। वर्तमान स्वीकृति के अंतर्गत एचईसी मेसर्स सीएनआईआईटीएमएएसएच के साथ सहयोग कर रही है जो रूसी सरकार का औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। इस सहयोग का एक महत्व यह है कि कई दशकों के बाद सामरिक रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में फिर से प्रवेश करेगी। तीन सालों में 1350 इंजीनियरों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण देने से यह प्रस्ताव संबंधित है जिनमें इलेक्ट्रो स्लैग री–मेलटिंग, वेल्डिंग गियर बॉक्स निर्माण तथा अविनाशकारी परीक्षण शामिल है। 50 करोड़ रुपए की परियोजना में सरकारी अंश 30 करोड़ रुपए का होगा, जिसे रूसी संस्थान को चार प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण में उनके ज्ञान संबंधी सहयोग के लिए दिया जाएगा। एचईसी अन्य हितधारकों इकाइयों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) में हस्ताक्षर करेगी तथा भारतीय निर्माण क्षेत्र के लाभ के लिए 9 पाठ्यक्रमों का संचालन भी करेगी। एक बार कार्यान्वित होने पर प्रशिक्षित लोग इस्पात, वेल्डिंग, गियर बॉक्स तथा एनडीटी के निर्माण में शामिल होंगे, जिससे करोड़ों की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी। ❑❑

रेल का सफर हो सकता है महंगा

रेल मंत्रालय इस बार के बजट में यात्री किराया 5 से 10 फीसदी तक बढ़ा सकता है। यात्री और मालभाड़े दोनों में कमी आने और 7वें पे–कमिशन के सुझावों से एक्स्ट्रा 32,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ने की वजह से इस पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो एसी फस्ट का किराया बजट एयरलाइन से भी ज्यादा हो जाएगा। पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रही रेलवे की मुश्किलें बढ़ाते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी 2015–16 के लिए ग्रॉस बजटीय सपोर्ट घटाकर 8,000 करोड़ रुपए कर दिया है। माल भाड़े और यात्री से रेलवे की कुल आमदनी इस साल जनवरी तक 1.36 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि इसका टारगेट 1.41 लाख करोड़ रुपए का है। रेलवे फिलहाल अपने टारगेट से 3.77 फीसदी पीछे है।

एथेनॉल ब्लेंडिंग का पहली बार हासिल होगा लक्ष्य

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि सरकारी फ्यूल रिटेलर्स पहली बार इस वर्ष पेट्रोल में 5 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को हासिल करने

जा रहे हैं। करीब एक दशक पहले पेट्रोल में 5 फीसदी एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य सरकार ने तय किया था। इंडियन ऑइल कॉर्प, भारत पेट्रोलियम कॉर्प और हिन्दुस्तान कॉर्प ने नंवबर 2015 से शुरू हुए शुगर इयर में मिलकर 120 करोड़ लीटर एथेनॉल की खरीदारी की है ताकि टारगेट को पूरा किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में एथेनॉल ब्लेंडिंग रेश्यो 3 फीसदी से नीचे रहा है।

कोका–कोला बंद

कोका कोला इंडिया की बॉटलिंग (बोतलबंद करने वाली) इकाई हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज ने दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता के अभाव का हवाला देते हुए भारत में तीन स्थानों पर विनिर्माण स्थगित कर दिया है जिससे करीब 300 कर्मचारी प्रभावित होंगे। कंपनी ने जयपुर (राजस्थान) के पास कालाडेरा, विशाखापटटनम (आंध्र प्रदेश) और ब्रिनिहाट (मेघालय) में विनिर्माण स्थगित किया है। जबकि अन्य परिचालन जारी रहेंगे। संयंत्र बंद करने का फैसला कारोबारी निर्णय है जो दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता और संयंत्र विशेष में विनिर्मित उत्पादों की बाजार मांग को ध्यान में रखकर लिया गया है।

फेसबुक फ्री बेसिक्स बंद

फेसबुक ने भारत में फ्री बेसिक्स बंद कर दिया है। सालभर पहले उसने अमरीका के बाहर अपने सबसे बड़े मार्केट भारत में इसे लांच किया था। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने अलग–अलग

डेटा सर्विसेज के लिए अलग–अलग रेट तय करने की हरकत पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इस आदेश के दायरे में जीरो–रेटेड़ प्रॉडक्ट्स भी हैं। इस कारण फेसबुक ने यह कदम उठाया। भारत में फेसबुक का एक महीने में एक्टिव यूजर्स बेस 13.8 करोड़ लोगों का है। अमरीका के बाहर यह सबसे बड़ी संख्या है।

घटेगी दर PPF, NSC जैसी छोटी सेंविंग्स स्कीम्स की

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) जैसी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरें 1 अप्रैल से घटने की उम्मीद है क्योंकि सरकार कहीं ज्यादा फ्रीक्वेंट मार्केट–लिंक्ड व्यवस्था का रूख कर रही है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स के तहत पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस फिक्सड डिपॉजिट स्कीम, सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट और सुकन्या समृद्धि अकाउंटस आती हैं। हालांकि गर्ल चाडल्ड और सीनियर सिटिजन स्कीम्स को इस बदलाव से बाहर रखा जायेगा।

24 घंटे बिजली की राह में अड़ंगा

साल 2022 तक 24 घंटे बिजली देने के लिए केंद्र सरकार देश में 12 नए अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट (यूएमपीपी) लगाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने यूएमपीपी की नई गाइडलाइंस का ड्राफ्ट जारी किया है, लेकिन बिजली

कंपनियों का कहना है कि इन गाइडलाइंस में दो बड़े मुद्दों से वे सहमत नहीं हैं और सरकार को गाइडलाइंस में संशोधन करना चाहिए। उसके बाद ही कंपनियां यूएमपीपी की बिडिंग में हिस्सा लेंगी। इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मांग यह है कि उन्हें प्लग–एंड–प्ले मोड पर यूएमपीपी अलॉट किया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बिड के कई साल बाद तक कंपनियों को जमीन अलॉट नहीं की जाती और जमीन मिल भी जाए तो तरह–तरह की क्लीयरेंस नहीं मिलती। इस मुद्दे को नई गाइडलाइंस में भी शामिल नहीं किया गया। गाइडलाइंस में स्पष्ट होना चाहिए कि यूमपीपी की बिड तभी होगी, जब सरकार के पास जमीन होगी और वहां प्रोजेक्ट लगाने से संबंधित सभी क्लीयरेंस सरकार के पास हों।

दिल्ली में फिर लागू होगा सम–विषम फार्मूला

दिल्ली में ऑड–ईवन स्कीम फिर से 15 से 30 अप्रैल को लागू होगी। दिल्ली सरकार ने प्रेस कांफ्रेंस कर सूचित किया कि ऑड–ईवन स्कीम का दूसरा फेज फिर से शुरू किया जाएगा। ऑड–ईवन स्कीम के रूल से महिलाओं

को छूट मिलेगी। ऑड–ईवन स्कीम का 80 फीसदी लोगों ने समर्थन किया था।

वायदा बाजार घटायेगा किसानों का जोखिम

विकसित वायदा बाजार से खेती के जोखिम को घटाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि उपज के मूल्यों के उतार–चढ़ाव से किसान हलकान रहता है, जिसकी मुश्किलें इससे कम हो सकती हैं। श्री

सिंह ने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी मुश्किल उनकी उपज के उचित मूल्य न मिलने की है। वायदा बाजार से उन्हें काफी सहूलियत मिल सकती है। हालांकि ज्यादातर किसान इन फ्यूचर मार्केट (वायदा बाजार) में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं ले पाते हैं, फिर भी उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। इन बाजारों में मौसमी मूल्यों के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। फसलों की कटाई के बाद उपज के मूल्यों में मंदी की मार से किसानों को बचाया जा सकता है। फिलहाल देश में 22 पंजीकृत वायदा एक्सचेंज हैं, जिनमें जिंसों का कारोबार होता है। इनमें से तीन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज प्रमुख हैं, जिन्हें भारत सरकार से मान्यता मिली हुई है। राधा मोहन सिंह ने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए एक ऐसा पोर्टल लांच किया गया है जो किसानों को उनकी भाषा में होगा। इसमें किसान खेती से जुड़ी हर छोटी–बड़ी सूचनाएं मांग सकते हैं। कमोडिटी एक्सचेंज की सफलता के लिए भंडारण प्रणाली बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार भंडारण विकास एवं नियामक प्राधिकरण को प्रोत्साहित कर रही है। फिलहाल इसमें 949 गोदाम पंजीकृत हैं।

पीएनबी को सर्वोत्तम बैंक पुरस्कार

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए सर्वोत्तम बैंक पुरस्कार जीता है। इसके लिए पुरस्कार समारोह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के चौंबर CIMSME ने आयोजित किया था। पुरस्कार बैंक के कार्यकारी निदेशक डॉ. राम एस संगापुरे ने केंद्रीय ऊर्जा, कोयला और अक्षय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और सीआइएमएसएमई के अध्यक्ष मुकेश मोहन गुप्ता से प्राप्त किया। पीएनबी को बड़े बैंकों में सीएसआर और कारोबार दायित्व के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक तथा सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक के लिए रनरअप भी घोषित किया गया।

रतन टाटा का ई–कॉमर्स कंपनी मोगलिक्स में निवेश

रतन टाटा ने दुनियाभर की स्टार्टअप कंपनियों में निवेश की पहल बरकरार रखते हुए औद्योगिक उत्पादों की खरीद से जुड़ी ई–कॉमर्स कंपनी मोगलिक्स में

निवेश किया है। इस वर्ष स्टार्ट–अप्स में टाटा का छठा निवेश है। इससे पहले उन्होंने पांच कंपनियों, डॉगस्पॉट डॉट इन, ट्रैक्स्न, कैशकारो, फर्स्टक्राई और टीबॉक्स में निवेश किया था।

लाफार्ज सीमेंट में ग्रेड रिवीजन

मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट) के ठेका श्रमिकों के दैनिक वेतन में बढ़ोतरी की गई है। कंपनी प्रबंधन और लाफार्ज इंडिया इम्प्लाइज यूनियन के बीच कंपनी के गेस्ट हाउस में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी पहली फरवरी 2016 से 31 दिसंबर 2017 तक प्रभावी होगी। ठेका कर्मचारियों का अंतिम ग्रेड रिवीजन 26 दिसंबर 2014 को हुआ था। इस नए समझौते के साथ झारखंड सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर कर्मचारियों के दैनिक वेतन में सीधे बढ़ोतरी की गई है। नए वेतन समझौते के तहत कर्मचारियों के वेतन में 15 रुपये से 70 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। झारखंड सरकार ने 15 अगस्त 2015 से न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की थी। लाफार्ज में इसे लागू करने के लिए लाफार्ज ठेका मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में ठेका कर्मचारी आंदोलनरत थे।

अमीरों से छीनी जाएगी गैस सब्सिडी

केंद्र सरकार सबसे पहले 10 महानगरों के अमीरों की गैस सब्सिडी खत्म करेगी। इसके तहत दिल्ली–

एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ और चंडीगढ़ को सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय सबसे पहले इन्हीं 10 शहरों में अमीरों के लिए गैस सब्सिडी समाप्त करेगी। इसके लिए तेल कंपनियों को उपभोक्ताओं से उनकी आय जानने के लिए एसएमएस और इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स (आईवीआर) भेजने को कहा गया है। साथ ही सिलेंडर बुक कराते समय फोन कॉल के समय भी आय को लेकर सवाल पूछने को कहा गया है। कंपनियों से महीने के मध्य तक इस पर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'इस आदेश की पालना के दौरान ध्यान रखा जाए कि बीपीएल और शहरी गरीबों को परेशानी न हो। ऐसे लोगों को आय बताने के लिए मजबूर न किया जाए। उच्च आय वाले लोगों को ही लक्ष्य पर रखा जाए।' केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 300510 उपभोक्ताओं की पहचान 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा सालाना आय वालों के रूप में की है। तीनों तेल कंपनियों से कहा गया है कि वे इन उपभोक्ताओं को खुद ही सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करें। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने कहा था कि नए साल से 10 लाख सालाना आय वाले उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी। इससे पहले पिछले साल मार्च में सरकार ने संपन्न लोगों से स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी। इसके तहत 69 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ी थी।

पतंजलि की FMCG कंपनियों के टैलंट पर नजर

बड़ी एफएमसीजी कंपनियों के बाजार पर कब्जा करने के बाद अब योगगुरू बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने उनकी वर्कफोर्स को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। पिछले 6

महीने में करीब 250 एग्जिक्युटिव्स ने बड़ी एफएमसीजी कंपनियों को छोड़कर पतंजलि को जॉइन किया है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्णा ने कहा कि हमारे यहां कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है। यहां स्पिरिचुअल कल्चर है।

कुली होंगे 'लगेज असिस्टेंट'

यात्रियों का सामान ढोने वाले पारंपरकि कुलियों का रेलवे स्टेशन पर दिखना जल्द ही इतिहास की बात हो जाएगी। रेलवे जल्द ही कुलियों को लेकर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करने की योजना बना रहा है। रेलवे की योजना के मुताबिक, इन कुलियों को ट्रॉली दी जाएगी। ये ट्रॉली वैसी ही होगी, जैसा कि एयरपोर्ट पर मिलती है। इन कुलियों को नया नाम भी मिलेगा। अगर योजना को अमली जामा पहनाया गया तो भवष्यि

में कुलियों को 'लगेज असस्टिेंट' के नाम से जाना जाएगा। रेलवे कुली नाम को इसलिए भी बदलना चाहता है कि क्योंकि यह औपनिवेशिक काल की याद दिलाता है। कुली लाल रंग की यूनिफॉर्म में बांह पर बिल्ला बांधे नजर आते हैं। रेलवे इनकी वेशभूषा में भी बदलाव कर सकता है। इसके तहत, इन्हें ऐसे कपड़े दिए जाएंगे जिस पर विभन्नि कंपनियों के विज्ञापन होंगे। रेलवे इस योजना पर विचार इसलिए कर रही है ताकि उसे अतिरिक्त राजस्व मिल सके।

सस्ता प्याज भी निकाल रहा आंसू

महाराष्ट्र के लासलगांव थोक बाजार में प्याज की कीमतें गिरकर 10 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे आ गईं हैं। लेकिन देश की राजधानी में उपभोक्ताओं को अब भी प्याज के लिए प्रति किलो 18–20 रुपये चुकाना पड़ रहा है। यानी आम आदमी को प्याज कीमतों पर खास राहत नहीं मिली है। मौजूदा वित्त वर्ष में प्याज कीमतों का यह सबसे निचला स्तर है। लासलगांव में प्याज की कीमतें सितंबर में 41.30 रुपये प्रति किलोगाम से 76 फीसदी गिरकर 9.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। नासिक स्थित नेशनल हार्टीकल्चरल एंड रिसर्च फाउंडेशन (एनएचआरडीएफ) के आंकड़ों के अनुसार थोक प्याज की कीमतें न्यूनतम 7 रुपये प्रति किलोग्राम और अधिकतम 14.22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा रहीं हैं।

हवाई सफर होगा सस्ता

जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से यात्रा करना सस्ता हो जाएगा। नियामक एईआरए ने हवाईअड्डा परिचालक को 1 मई से विकास शुल्क लगाना बंद करने को कहा है। वर्तमान में आईजीआई हवाईअड्डे से घरेलू यात्री को प्रति उड़ान 100 रूपये विकास शुल्क के तौर पर देना पड़ता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह शुल्क 600 रुपये है। विकास शुल्क के तौर पर प्रतिमाह 30 करोड़ रुपये के औसत संग्रह का हवाला देते हुए नियामक ने कहा कि कुल मंजूर विकास शुल्क 30 अप्रैल, 2016 तक 3,415 करोड़ रुपये के वसूल होने की संभावना है।

मैगी के बाद होरलिक्स फूडलेस फेल

नेस्ले इंडिया के बाद उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कई फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों की जांच कराई गई, जिसमें से कुछ प्रोडक्टों में कमी पाई गई। फूड सिक्युरिटी ऑफीसर संजय सिंह ने बताया कि पिछले साल मई में शहर के एक माल से नॉर के सूपी नूडल्स, हॉर्लिक्स के फूडल्स और चिंग्स के हॉट गार्लिक इंस्टेंट नूडल्स के नमूने लेकर जांच के लिये भेजे थे, जिनकी रिपोर्ट हाल में ही आयी है। जांच में इन सभी उत्पादों के नमूने मानकों से नीचे

पाए गए। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि इन उत्पादों के टेस्टमेकर की भस्म की मात्रा एक प्रतिशत की अनुमान्य मात्रा से ज्यादा पायी गयी है। सिंह ने बताया कि चिंग्स नूडल्स के टेस्टमेकर की भस्म की मात्रा 1.83 प्रतिशत, हॉर्लिक्स फूडल्स में 2.37 फीसद और नॉर सूपी नूडल्स में .89 प्रतिशत पायी गयी है, लिहाजा इन्हें अधोमानक माना गया है। इन कंपनियों को बाराबंकी कार्यालय से एक हफ्ते पहले नोटिस जारी किया गया है। इन मानकों से कमतर उत्पादों के सेवन से सेहत को होने वाले नुकसान के बारे में पूछने पर सिंह ने बताया कि रिपोर्ट में यह नहीं लिखा गया है कि इनसे स्वास्थ्य को क्या नुकसान होगा, लिहाजा वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकते।

बिन बीमा कागजात के दौड़ा सकेंगे वाहन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम को बढ़ावा देने के लिए आईआरडीए वाहन के कागजों को डिजिटल फोर्मेट में करने में जुट गया है। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ई–वाहन बीमा योजना की शुरूआत की है। इसके बाद वाहन स्वामियों को कार या दो पहिया वाहन सड़क पर ले जाते वक्त बीमा के कागजात साथ रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हालांकि यह योजना केवल तेलंगाना में शुरू हुई है। आईआरडीए धीरे–धीरे इसे अन्य राज्यों में शुरू करने की कवायद में जुटी है। ई–वाहन बीमा योजना के अंतर्गत मोटर गाडियों के बीमा को ऑनलाइन जारी किया जाता है। इसमें एक क्विक रेस्पोंस (QR) कोड वाहन बीमा कराने वाले के नंबर पर भेजा जाता है। इस कोड में पॉलिसी की पूरी डिटेल दी जाती है और यातायात पुलिस इस कोड को स्कैन कर वाहन की पूरी जानकारी ले लेटी है।❑❑

चीन से चुनौती और स्वदेशी समाधान

स्वदेशी जागरण मंच, लुधियान की ओर से दिनांक 20 जनवरी 2016 को सायं 4.30 बजे, सरकट हाउस, फिरोजपुर रोड़, अंसल प्लाजा के सामने, लुधियाना में 'चीन एक चुनौती और स्वदेशी समाधान' विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्री कश्मीरी लाल (अखिल भारतीय संगठक) मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने संबोधन में स्वदेशी की महत्ता का उल्लेख करते हुए परिवार में स्वदेशी के चलन पर बल दिया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को श्री सतीश कुमार (त्री क्षेत्र संगठक एवं अखिल भारतीय सह विचार मंडल प्रमुख) का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। ❑

महिला सम्मेलन, नागपूर

मकर संक्रांति के अवसर पर नागपुर (महाराष्ट्र) ईकाई के तत्वाधान में दिनांक 17 जनवरी 2016 को महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। श्रीमति अंजलि मासे ने कार्यक्रम का संचालन किया। डॉ. श्रीमति अमिता पत्की ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि बाजार में चीनी वस्तुओं की आई बाढ़, देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि जब वे बाजार जाएं तो वे विक्रेताओं से भारतीय ब्रांड की ही वस्तु खरीदे। श्रीमति माधवी, श्रीमति रेणु पुराणिक, श्रीमति शारदा, श्रीमति जयश्री, श्रीमति जयश्री गुप्ता, डॉ. श्रीमति रमा, श्रीमति वर्षा राजकरने तथा श्रीमति काले तथा श्रीमति वसुधा भिंडे कार्यक्रम में उपस्थित रही। श्री आशुतोष पाठक ने जनवरी 2016 में आयोजित महिला सम्मेलनों के बारे में विस्तरित जानकारी प्रस्तुत की। ❑

परिवार सम्मेलन, जमशेदपुर (झारखंड)

स्वदेशी जागरण मंच जमशेदपुर के द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2016 को 300 परिवारों की सहभागिता से मानगो गांधी घाट पर ''परिवार सम्मेलन'' का आयोजन किया गया। सम्मेलन में झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री सरयु राय ने कहा कि संयुक्त परिवार ही भारत की वास्तविक पूंजी है। भौतिक सुख वास्तविक सुख नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता है कि भारतीय परिवार व्यवस्था बची रहे और स्वदेशी जागरण मंच इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है।

कार्यक्रम में श्री बंदेशंकर सिंह ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से प्रयास करता रहा कि भारत की परिवार व्यवस्था और समाज बचा रहे तथा आर्थिक रूप से समृद्व रहे। श्री मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रकृति जरूरत को पूरा कर सकती है मनुष्य के लालच को नहीं। इस अवसर पर जेकेएम राजू, राजकुमार साह, सीपी सिंह, अमित मिश्रा, कौशल किशोर, गौरव शंकर, राकेश पांडे, रौशन सिंह, अभिषेक बजाज, अभय सिंह, विजय सिंह, रामेश्वर प्रसाद, संजीत प्रमाणिक, सत्यनारायण मिश्रा, पंकज सिंह, सुरेन्द्र सिंह, जयंत श्रीवास्तव, सुखदेव सिंह, कमलेन्दु सर, सोनु ठाकुर, संजय तिवारी, राजीव सिंह, बाब्ला सिंह, अजय गुप्ता, मंजु ठाकुर, राजपति देवी, प्रीति सिन्हा, अंजु सिंह, ममता सिंह, सुनिता सिंह, अनामिका शर्मा, विजया लक्ष्मी, रजनी मिश्रा, मुन्नी ठाकुर, उर्मिला ठाकुर, राजेश कुमार, सुनील कुमार, आशुतोष राय, सहित स्वदेशी परिवार और समविचारी संगठनों के प्रमुख लोग उपस्थित थे। ❑❑